# सुबह सवेरे

A Daily News Magazine
इंदौर
शनिवार, 19 अप्रैल, 2025

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 10 अंक 189, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2



subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews


प्रसंगवश

## चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध क्या फौजी जंग में तब्दील होगा?

**जनरल मनोज नरवणे (रि)**

अमेरिका ने पिछले सप्ताह टैरिफों की जो बौछार की उसने दुनिया भर के बाज़ारों में खलबली मचा दी। चीन ने जवाबी टैरिफों की घोषणा की, जिसके बाद अमेरिका ने टैरिफों में और वृद्धि कर दी और इस तरह उनमें कुल 104 फीसदी की वृद्धि कर दी। 9 अप्रैल को अमेरिका ने 'मुक्ति दिवस' पर चीन को छोड़ बाकी सभी देशों के लिए टैरिफों में वृद्धि पर 90 दिनों के लिए विराम की घोषणा कर दी।

चीन जबकि इस टैरिफ धमकी के आगे हथियार डालने के कोई संकेत नहीं दे रहा, तब सवाल उठता है कि क्या यह व्यापार युद्ध वार्ता की मेज तक ही सीमित रहेगा या यह और तेज़ हो सकता है? व्यापार युद्ध अक्सर दो देशों के बीच तनाव में बदलता रहा है। वास्तव में, यह सीधी सैन्य युद्ध की जगह कूटनीतिक युद्ध जैसे होते हैं, लेकिन व्यापार युद्ध अगर तीखा हुआ तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं जो इसे वास्तविक युद्ध में बदल सकते हैं। विशेष तौर पर, घरेलू आर्थिक परेशानियां अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं को उभारती हैं और तब देश अपने हितों की रक्षा के लिए या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए रक्षात्मक या आक्रामक रुख अपनाते हैं। व्यापारिक विवाद भू-राजनीतिक तनावों को जन्म देता है, जो सैन्य युद्ध भड़का सकता है। यह बात खासकर तब लागू होती है जब व्यापार असंतुलन, बाज़ार तक पहुंच, रणनीतिक संसाधनों, खासकर मूल्यवान खनिजों (जिनके निर्यात पर चीन ने पूर्ण रोक लगाने की घोषणा कर दी है) और टेक्नोलॉजी जैसे मसलों को लेकर टकराव पैदा होता है।

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध व्यापक भू-राजनीतिक होड़ से भी गहराई से जुड़ा है। चीन के उभार को अमेरिका दुनिया में अपने वर्चस्व के लिए एक रणनीतिक चुनौती के रूप में देखता है। खासकर 'बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव' (बीआरआई) जैसे कार्यक्रमों के जरिए चीन जिस तरह तकनीक और आर्थिक शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है उसने स्थिति को और जटिल बना दिया है। अमेरिका को चिंता है कि आर्थिक रूप से मजबूत चीन एक सैन्य शक्ति भी बन जाएगा, उधर चीन को लगता है कि अमेरिका उसके विकास को रोकना चाहता है। यह 'थुसिडाइड ट्रैप' का निर्माण करता है।

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध उन्हें अपने आर्थिक हितों या क्षेत्रीय दावों की रक्षा के लिए अपनी सैन्य तैनाती मजबूत करने को प्रेरित कर सकता है। दक्षिण चीन सागर और ताइवान क्षेत्र में सैन्य तनाव के कारण दोनों के रणनीतिक हित टकराते हैं। अकेले टैरिफ वॉर के कारण सीधी लड़ाई शुरू होने की संभावना कम है, लेकिन आर्थिक प्रतियोगिता ऐसे छद्म युद्ध के लिए आधार तैयार कर सकती है, जो कभी भी छिड़ सकता है। जब चीन जैसी उभरती शक्ति अमेरिका जैसी स्थापित शक्ति की जगह लेने की चुनौती दे रही है तब, जैसा कि अमेरिकी राजनीतिशास्त्री ग्राहम टी. एल्लिसन कहते हैं, इससे उत्पन्न तनावों के कारण हिंसक टकराव अपरिहार्य है।

अमेरिका-चीन टकराव, और जापान-अमेरिका युद्ध के कारणों के बीच कुछ समानता है. द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले के दशकों में जापान एशिया में अपनी जिन साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उसके कारण इस क्षेत्र में अमेरिका के हितों से उसका टकराव हो रहा था। दक्षिण-पूर्व एशिया में जापान के आक्रामक विस्तार और तेल, रबर, खनिजों आदि के लिए बढ़ती उसकी ख्वाहिशों के कारण अमेरिका से उसका तनाव बढ़ता जा रहा था। अमेरिका ने जापान की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाने के जवाबी कदम उठाते हुए उस पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए थे और साथ में तेल तथा स्टील पर भी रोक लगा दी थी।

अमेरिकी प्रतिबंधों और प्रतिबंधात्मक व्यापारिक नीतियों से खतरा महसूस करते हुए जापान ने संसाधनों तक अपनी पहुंच सुरक्षित करने के लिए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपना विस्तार करने की कोशिश की। उसने दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की तरह, चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति को भी दुनिया में अमेरिका के वर्चस्व के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। चीन जिस तरह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़त ले रहा है, दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। उसकी जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं (खासकर ताइवान को लेकर) वह द्वितीय विश्वयुद्ध वाले दौर में जापान के विस्तारवादी लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करती हैं।

अमेरिका-चीन का व्यापार युद्ध टेक्नोलॉजी हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा, और बाजार में हिस्सेदारी जैसे मसलों के इर्द-गिर्द केंद्रित है. ये मसले जापान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से, जिनका मकसद रणनीतिक संसाधनों और टेक्नोलॉजी को निशाना बनाना था, जुड़े मसलों के समान ही हैं। जैसे जापान ने अमेरिकी प्रतिबंधों को अपने विस्तार के लिए खतरा माना था, वैसे ही चीन मानता है कि वैश्विक वर्चस्व की उसकी दीर्घकालिक योजना के लिए अमेरिकी नीतियां खतरा हैं, क्योंकि वह आधुनिक टेक्नोलॉजी और बाज़ार तक उसकी पहुंच में रणनीतिक बाधाएं हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया में जापान के सैन्य विस्तार की तरह, दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती दावेदारी को अमेरिका और उसके 'क्वाड' सहयोगियों के साथ चीन के तनाव की बड़ी वजह माना जा रहा है।

चीनी नौसेना पीएलए ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करने वाले तस्मान सागर में फरवरी 2025 में असली युद्ध जैसा नौसैनिक युद्धाभ्यास किया। इसे 'असामान्य और उकसाऊ' कार्रवाई बताया गया। हालांकि, इस तरह के उकसावों से सीधी लड़ाई नहीं छिड़ी है, लेकिन इनके कारण बड़े टकराव की आशंका बनी हुई है, खासकर इसलिए कि अमेरिका इन्हें अपने सहयोगियों और अपने हितों के खिलाफ चुनौती के रूप में देखता है।

तो अब आगे क्या होगा? अमेरिका ने टैरिफों के मामले में जो रियायत बरती है वह क्या निर्णायक हो सकती है, क्योंकि आधुनिक काल में आर्थिक युद्ध के बाद प्रायः वास्तविक युद्ध होता ही रहा है? फिलहाल दोनों देशों ने जो सख्त रुख अपना रखा है उसमें व्यापार से संबंधित रियायतें चीन का हौसला और बढ़ा ही सकती हैं। चीन का उत्कर्ष मुख्यतः उसकी दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति की देन है, जिसका लक्ष्य प्रमुख सेक्टरों में अपना वर्चस्व कायम करना है। अगर अमेरिका चीन को टैरिफ खत्म करने या बाज़ार में प्रमुखता से हिस्सेदारी देने की पेशकश करता है तो ज्यादा संभावना यह है कि चीन इसे उसकी कमजोरी माने। यह उसे ताइवान, टेक्नोलॉजी आदि के मसलों पर ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने और अपनी सैन्य शक्ति जताने तक को भी प्रेरित कर सकता है, जैसा कि उसने तस्मान सागर में किया था। अब देखना यह है कि पहले कौन झुकता है, ताकि दो देश उस लड़ाई में न उलझें जिसे कोई नहीं चाहता।

**(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)**

## बदल रहा है इलेक्शन कमीशन! अब सुधारों की बढ़ गई है उम्मीद

### मुख्य चुनाव आयुक्त ने अंतरराष्ट्रीय चुनावी प्रक्रियाओं का शुरू किया अध्ययन

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** भारतीय चुनाव आयोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया का संचालन करता है। यह अब एक नई दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यभार संभालते ही चुनाव आयोग में कई बड़े और निर्णायक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसका उद्देश्य न केवल भारत की चुनाव प्रणाली को अधिक पारदर्शी और बेहतर बनाना है, बल्कि इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप या उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर रूप में तैयार करना है। इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सबसे पहले चुनावी प्रक्रियाओं के अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को प्रत्येक लोकतांत्रिक देश की चुनाव प्रणाली का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। इसका मकसद यह जानना है कि उन देशों में चुनाव कैसे होते हैं, मतदाता सूची कैसे बनती है, और वे कौन-सी नई चीजें और नए तरीके अपनाते हैं जो भारत के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं।

- **एक राष्ट्र, एक चुनाव की दिशा में मतदाता सूची की एकरूपता पर दे रहा जोर**

### प्रत्येक मतदाता को भागीदार बनाने की पहल!

अपने इस पहल के माध्यम से चुनाव आयोग भविष्य में भारतीय चुनावी प्रक्रिया में और भी आधुनिक तकनीकों, जैसे ऑनलाइन वोटिंग, रियल-टाइम वोट ट्रैकिंग या डेटा-संचालित प्रबंधन को शामिल कर सकता है। इससे चुनाव प्रणाली को और भी ज्यादा विश्वसनीय और मतदाता-अनुकूल बनाया जा सकता, ताकि देश का हर वोटर मतदान की प्रक्रिया में भागीदार बन सके।

### एक राष्ट्र, एक चुनाव की ओर बढ़ते कदम

दूसरा महत्वपूर्ण कदम है विभिन्न राज्यों में स्थानीय निकाय चुनावों के नियमों की समीक्षा। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि देश में एक समान मतदाता सूची तैयार करने की दिशा में यह पहला और बुनियादी कदम होगा। अभी तक स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अलग मतदाता सूचियां होती हैं, जो कई बार लोकसभा और विधानसभा चुनावों से भिन्न होती हैं। अगर पूरे देश में ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक एक ही मतदाता सूची का इस्तेमाल होगा, तो न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि इससे मतदाता सूची में डुप्लिकेशन और गड़बड़ियों की संभावना भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। यह एक राष्ट्र, एक चुनाव की दिशा में एक बुनियादी कदम की तरह है। चुनाव आयोग अपने हेडक्वार्टर की कार्य संस्कृति को भी अधिक अनुशासित और आधुनिक बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। अब इसके सभी कर्मचारी ई-ऑफिस सिस्टम का उपयोग करेंगे और उनकी उपस्थिति बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (बीएएस) से दर्ज होगी।

## पीएम मोदी ने एलन मस्क से की तकनीकी सहयोग पर चर्चा

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के साथ हुई अपनी बातचीत की जानकारी साझा की। पीएम ने बताया कि वाशिंगटन डीसी में इस साल हुई उनकी पिछली मुलाकात के दौरान कुछ खास मुद्दों पर भी बात हुई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में भारत और अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग की बहुत संभावना बताई। पीएम मोदी ने लिखा, एलन मस्क से बात हुई और कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें वाशिंगटन डीसी में इस साल हुई हमारी मुलाकात के दौरान शामिल विषय भी शामिल थे। उन्होंने आगे कहा, हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा की। इसका मतलब है कि भारत और अमेरिका मिलकर टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत, अमेरिका के साथ इन क्षेत्रों में अपनी दोस्ती को और आगे बढ़ाएगा। यह बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर एक समझौता होने की बात चल रही है। खबर है कि टेस्ला जल्द ही भारतीय बाजार में आ सकती है। लेकिन पीएम मोदी के पोस्ट में इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई न ही यह बताया गया कि कंपनी की भारत के लिए क्या योजनाएं हैं।

## वन प्रबंधन में औपनिवेशिक सोच से मुक्त होना जरूरी : मुख्यमंत्री

### पृथ्वी पर निवासरत प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा, अन्न और जल को सुरक्षित रखना होगा : केन्द्रीय मंत्री यादव



**भोपाल (नप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वन, आजीविका से सम्बद्ध विषय है। जनजातीय क्षेत्र में अपार वन संपदा उपलब्ध है। इसके प्रबंधन में ध्यान रखना होगा कि विकास से जनजातीय वर्ग के हित प्रभावित न हो। भारतीय जीवन पद्धति वनों पर आधारित रही है। वनों के प्रबंधन में औपनिवेशिक सोच से मुक्त होने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विरासत से विकास और प्रकृति को जोड़ते हुए प्रगति और प्रकृति में सामंजस्य स्थापित कर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। पेसा एक्ट इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि जीवन का आनंद समग्रता में है, और प्रकृति आधारित जीवन जीने से कई समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जनजातीय क्षेत्रों में वन पुर्नस्थापना, जलवायु परिवर्तन और समुदाय आधारित आजीविका पर प्रशासन अकादमी में राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव तथा केन्द्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर तथा भगवान बिरसा मुंडा और वीरांगना रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। प्रदेश के महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, केन्द्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उईके भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में वनों की स्थिति में सुधार और वन प्रबंधन में नवाचार के लिए के लिए वन विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों के संरक्षण से इको सिस्टम बेहतर हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर चीतों का पुर्नस्थापना हो पाया है। उन्होंने किंग कोबरा सहित रैप्टाइल्स की प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता जताते हुए कहा कि इससे सर्पदंश की घटनाओं में कमी आएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वन क्षेत्र में विद्यमान जनजातीय समुदाय के पूजा और आस्था स्थलों के संरक्षण के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। आवश्यकता होने पर केंद्र शासन से भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश वन की दृष्टि से बहुत संपन्न है। प्रदेश में यद्यपि कोई ग्लेशियर नहीं है, किन्तु प्राकृतिक रूप से वनों से निकलने वाली जल राशि से ही प्रदेश से निकलने वाली बड़ी नदियां आकार लेती हैं।

### महाकौशल में सर्पदंश से हो रहीं सबसे ज्यादा मौतें : सीएम

कार्यशाला में मौजूद अफसरों से सीएम ने कहा- सर्पों की गिनती चालू कराएं। ये अभी तक फॉरेस्ट एक्ट में ही नहीं हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट में है लेकिन गिनती नहीं करते। मैं दो चार बार बोल चुका हूं तो कहते हैं कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं हैं। मैं पूछता हूं कि ये जानवर नहीं हैं या इसका कोई हिसाब- किताब ही नहीं हैं।सीएम ने कहा- व्यक्ति भी गया और आर्थिक दृष्टि से मदद करने के लिए 4 लाख की मदद देना होती है। सवाल राशि का नहीं है, बड़े पैमाने पर लोगों के मरने का है। उनको सुविधा देने का है। अंदरूनी क्षेत्रों में रहने वाले लोग घबराकर शहरी क्षेत्र में आ रहे हैं। जब हमने पूछा कि इतने अच्छे प्राकृतिक वातावरण में क्यों नहीं रह रहे हैं? तो पता चला कि जहरीले सांपों की संख्या बढ़ी है।

### सुप्रभात

हक़ मेरी मोहब्बत का अदा
क्यूँ नहीं करते
तुम दर्द तो देते हो दवा
क्यूँ नहीं करते
क्यूँ बैठे हो ख़ामोश
सिरहाने मेरे आ कर
यारो मिरे जीने की
दुआ क्यूँ नहीं करते
फूलों की तरह जिस्म है
पत्थर की तरह दिल
जाने ये हसीं लोग वफ़ा
क्यूँ नहीं करते
हर बात परिंदों की
तरह उड़ती हुई सी
जो बात भी करते हो सदा
क्यूँ नहीं करते
लो देखो 'हमीदी'
लब–ए–दरिया पे है दरिया
पर प्यास है कब की ये पता
क्यूँ नहीं करते।

– अनवार हमीदी

## पत्नी के साथ जयपुर में 3 दिन रहेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति

### बिल क्लिंटन जैसा होगा स्वागत,आमेर किले के बंद गेट खुलवाए गए



**जयपुर (एजेंसी)।** अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस 21 अप्रैल को जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। वे तीन दिन जयपुर में रहेंगे और 23 अप्रैल को जयपुर से आगरा ताजमहल देखने जाएंगे। अमेरिकी वाइस प्रेसीडेंट भारतीय मूल की अपनी पत्नी उषा चिलुकुरी के साथ आमेर महल और जंतर-मंतर जैसी हेरिटेज साइट देखने भी जाएंगे।

इससे पहले 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी जयपुर आए थे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन भी अपने कार्यकाल के दौरान जयपुर दौरे पर आ चुके हैं। जेडी वेंस के दौरे के मद्देनजर सभी सुरक्षा एजेंसिया सतर्क हो गई हैं। आमेर फोर्ट में एजेंसियों ने सुरक्षा की तैयारियां देखी। व्हाइट हाउस ने वेंस के जयपुर दौरे की दो दिन पहले पुष्टि की थी।

सूत्रों के अनुसार, वेंस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर आ सकते हैं। जेडी वेंस की विजिट को लेकर अमेरिकी सेना के भी बड़े विमान यहां पहुंचे थे।

### 190 साल पुराने रामबाग पैलेस में रुकेंगे वेंस

दुनिया के टॉप लग्जरी होटल में शुमार रामबाग पैलेस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति का दो दिन स्टे होगा। करीब 190 साल पुरानी यह प्रॉपर्टी जयपुर के पूर्व राजपरिवार से संबंध रखती है। ताज ग्रुप का यह प्राइम होटल हॉलीवुड-बॉलीवुड स्टार्स के साथ दुनियाभर के सेलिब्रिटीज की पसंद है। अपने आखिरी दिनों में पूर्व महारानी गायत्री देवी भी रामबाग पैलेस में मौजूद लिलिपूल पैलेस में रहती थीं। रामबाग पैलेस को भारत का सबसे महंगा होटल माना जाता है।

### 'चंदा' और 'पुष्पा' करेंगी वेलकम

22 अप्रैल को आमेर महल विजिट के दौरान वे राजस्थानी मेहमान नवाजी का भी एक्सपीरियंस करेंगे। इस दौरान आमेर महल के सूरजपोल गेट पर उनका स्वागत हथिनी चंदा और पुष्पा करेंगी। हाथी गांव विकास समिति के अध्यक्ष बल्लू खान ने बताया कि दोनों हाथियों को चांदी के होदे लगेंगे और ज्वेलरी पहनाई जाएगी। आमतौर पर वीवीआईपी मेहमानों का स्वागत इसी तरह किया जाता है। आमेर के पास मौजूद हाथी गांव में सेरेमनी को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। जयपुर में उपराष्ट्रपति वेंस आमेर महल को घूमने में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। सूत्रों के अनुसार वे इस फोर्ट में करीब ढाई घंटे तक रुकेंगे। करीब 433 साल पुराना यह किला राजपूताना इतिहास के कई पन्नों को समेटे हुए है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के जयपुर दौरे से पहले एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ा दिया गया है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 22 °c | न्यूनतम 16°c


# सुबह सवेरे

इंदौर ■ शनिवार, 19 अप्रैल 2025


जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

## दिल्ली के सीलमपुर में युवक की हत्या के बाद तनाव

● परिजन का आरोप-कई मुस्लिम लड़कों ने रंजिश में मारा

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार शाम करीब 8 बजे 17 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इससे इलाके में तनाव है।

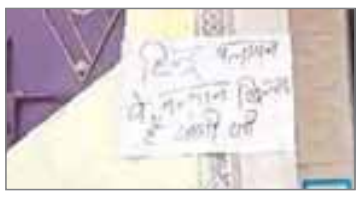

परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर चक्काजाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मुस्लिम लड़कों ने पुरानी रंजिश में हत्या की है। उधर, सीलमपुर में रहने वाले परिवारों ने घरों के बाहर हिंदू पलायन के पोस्टर लगाए हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। इन पोस्टर्स पर लिखा है, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो।

## तेलंगाना-हरियाणा के बाद आंध्र में भी आरक्षण में सब-कोटा

● अध्यादेश जारी; सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया कदम

**अमरावती (एजेंसी)।** आंध्र प्रदेश ने गुरुवार को अनुसूचित जातियों आरक्षण के भीतर आरक्षण देने के लिए अध्यादेश जारी

किया। राज्य में कुल 59 एससी जातियों को 15 फीसदी आरक्षण मिलता है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एससी और अनुसूचित जनजातियों कोटे में कोटा देने की अनुमति दी थी। आंध्र प्रदेश के अध्यादेश में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए एससी जातियों को तीन ग्रुप में बांटा गया है।

## धार्मिक नाम पर आवंटित वक्फ संपत्तियों पर बने हैं मकान-दुकान

● यूपी के जिलों से आने लगी रिपोर्ट,761 से अधिक संपत्तियां हैं शामिल

**लखनऊ (एजेंसी)।** यूपी के जिलों से जिलाधिकारियों ने धीरे-धीरे वक्फ संपत्तियों की जानकारी शासन को भेजनी शुरू कर दी है। शासन को अब तक मिली जिलों की रिपोर्ट के मुताबिक धार्मिक, शैक्षिक कामों

और कब्रिस्तान के लिए दी गई 761 से अधिक संपत्तियों पर घर और दुकानें बना दी गई हैं। शासन ने जिलाधिकारियों से वक्फ संपत्तियों के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी है। इसमें पूछा गया है कि वक्फ की संपत्तियों का आवंटन के बाद मनमाना इस्तेमाल किया जा रहा है। जिलाधिकारियों से अपने-अपने जिलों में स्थित वक्फ संपत्तियों की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे।

## अमेरिका ने खालिस्तान पर खोली आईएसआई की पोल

● एफबीआई के हत्थे चढ़ा बब्बर खालसा का आतंकी हरप्रीत भारत को बड़ी सफलता

**वॉशिंगटन (एजेंसी)।** भारत में आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार खालिस्तानी आतंकवादी हरप्रीत सिंह अमेरिका में गिरफ्तार हुआ है। अमेरिकी की संघीय जांच एजेंसी ने हरप्रीत को सैक्रामेंटो में गिरफ्तार किया। एफबीआई ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उसे भारत में लीगल अटैचे कार्यालय के एजेंटों ने सूचना दी थी कि हरप्रीत सिंह पंजाब, भारत में कई आतंकी हमलों के सिलसिले में वांछित था। दिलचस्प बात है कि हरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही अमेरिकी जांच एजेंसी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से खालिस्तानियों के कनेक्शन की पोल भी खोल दी है। एफबीआई ने बयान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का सीधा जिक्र किया है।

# मुस्लिमों की ही सुनी,तब बनाया है वक्फ कानून

### पीएम ने कहा-1700 शिकायतें मिलने के बाद बना है वक्फ एक्ट

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 सैकड़ों शिकायतों के बाद लाया गया है, जिनमें मुस्लिम समुदाय के लोगों,

● पीएम बोले-विशेष रूप से महिलाओं-विधवाओं की रही प्रमुख भूमिका

विशेष रूप से महिलाओं और विधवाओं की प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था में उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री ने यह बात दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने बताया कि 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें विभिन्न मुस्लिम समुदायों से वक्फ संपत्तियों को लेकर 1700 से अधिक शिकायतें मिली थीं, जिससे सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा, नया कानून इन शिकायतों का जल्द समाधान करेगा और सबसे गरीबों का आशीर्वाद मिलेगा। मैं पहले से ही उन पीड़ितों के लिए लड़ रहा हूं, विशेष रूप से विधवाओं के लिए जिन्हें पुराने कानूनों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया।

### कई जगह वक्फ कानून को लेकर भारी विरोध

हालांकि, वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर देश के कुछ हिस्सों में विरोध भी देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कानून को मुस्लिम विरोधी करार देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि यह कानून देश को बांटने वाला है और इसे लागू नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कानून का स्वागत करते हुए कहा कि यह वक्फ संपत्तियों से अमीर और प्रभावशाली मुस्लिमों द्वारा किए गए अतिक्रमण को खत्म करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने विशेष रूप से वक्फ-बाय-यूजर श्रेणी को हटाने, गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने और संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण करने के लिए राज्य को दी गई।

# 10,000 की भीड़ हुई जमा छीन ली पुलिस की पिस्तौल

### वक्फ हिंसा पर हाईकोर्ट में ममता सरकार का कबूलनामा

**कोलकाता (एजेंसी)।** वक्फ संशोधन ऐक्ट के खिलाफ पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पर राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि हिंसा के दिन करीब 10,000 की भीड़ जमा हो गई थी। इतना ही नहीं उन्मादी भीड़ ने तब मौके पर तैनात पुलिस की पिस्तौल भी छीन ली थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्मादी भीड़ में से करीब 10 लोगों के पास घातक हथियार थे, जिनसे पुलिस को अपने अधिकारियों को बचाना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि उपद्रवियों की हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले करीब 8000-10000 लोगों की भीड़ पीडब्ल्यूडी ग्राउंड आउट पर इकट्ठा हुई। इसके बाद भीड़ का एक हिस्सा अलग हो गया और करीब 5000 लोग उमरपुर की ओर बढ़ गए और एनएच को जाम कर दिया। इसके बाद देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और गंदी भाषा का इस्तेमाल करने लगी। इसके बाद उन्होंने पुलिस कर्मियों पर ईंट-पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस बीच, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक-एक सदस्य वाली तीन सदस्यीय समिति लोगों के पुनर्वास पर बात करे।

# अधर में लटकी कर्नाटक की जाति जनगणना

### अभी जारी नहीं होंगे नतीजे,2 मई को अगली बैठक

**बेंगलुरु (एजेंसी)।** कर्नाटक सरकार ने जाति जनगणना (सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण) के नतीजों को स्वीकार करने पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। गुरुवार को आयोजित विशेष मंत्रिमंडल बैठक में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब इस मामले पर अगली चर्चा 2 मई को होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में होगी। कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल ने सर्वेक्षण के तकनीकी विवरण और अतिरिक्त जानकारी की मांग की है, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 2 मई की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। पाटिल ने कहा, चर्चा अधूरी रही, लेकिन यह सौहार्द्रपूर्ण

थी। हमने विभिन्न समुदायों की जनसंख्या, उनके पिछड़ापन और अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आंकड़ों को लेकर उठाए गए विवाद इस चर्चा का हिस्सा नहीं थे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मंत्रियों से सर्वेक्षण पर अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने को कहा गया है।

### वोक्कालिगा और वीरशैव-लिंगायत समुदायों ने किया विरोध

गौरतलब है कि वोक्कालिगा और वीरशैव-लिंगायत समुदायों ने इस सर्वे को अवैज्ञानिक बताते हुए इसे खारिज करने और एक नया सर्वेक्षण कराने की मांग की है। पाटिल ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली कैबिनेट बैठक 24 अप्रैल को एम एम हिल्स में होगी, लेकिन उस बैठक में सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा नहीं की जाएगी। उस बैठक में पुराने मैसूर क्षेत्र से संबंधित मुद्दे लिए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट मंत्रियों से कहा गया है कि वे सर्वेक्षण को लेकर अपनी राय लिखित रूप में 2 मई की बैठक में प्रस्तुत करें।

### 1.38 करोड़ परिवारों के 5.98 करोड़ लोग शामिल

11 अप्रैल को बहुप्रतीक्षित सामाजिक-आर्थिक एवं शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट को कर्नाटक कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया था। पिछड़ा वर्ग विकास मंत्री शिवराज तंगादागी के अनुसार, जाति जनगणना रिपोर्ट 50 खंडों में है। इसमें 1.38 करोड़ परिवारों के 5.98 करोड़ लोग शामिल हैं। तंगादागी ने संवाददाताओं से कहा, ''इसमें 94.77 प्रतिशत लोग शामिल हैं। केवल 5.23 प्रतिशत लोग इसके दायरे से बाहर हैं।'' उन्होंने कहा कि जाति जनगणना 1.6 लाख अधिकारियों की मदद से तैयार की गई थी, जिसमें 79 आईएएस अधिकारी, 777 वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, 1,33,825 शिक्षक और कृषि एवं अन्य विभागों के 22,190 कर्मचारी शामिल थे। सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट पिछले साल फरवरी में कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के. जयप्रकाश हेगड़े द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को सौंपी गई थी। समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा भी इस सर्वेक्षण पर आपत्ति जताई गई है तथा सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर से भी इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। हालांकि, सभी वर्ग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। दलितों और ओबीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता और संगठन इसके समर्थन में हैं और चाहते हैं कि सरकार सर्वेक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक करे और इस पर आगे बढ़े।

### वाड्रा के खिलाफ तीन मामलों में ईडी की चार्जशीट तैयार

# गुरुग्राम से लंदन तक मनी लॉन्ड्रिंग का खेल!

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अपनी जांच को और तेज कर दिया है। ईडी जल्द ही वाड्रा के खिलाफ तीन अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। गुरुग्राम लैंड डील केस सहित इन मामलों में वाड्रा से लगातार तीसरे दिन पूछताछ की गई, जो कुल मिलाकर 16 घंटे चली। ईडी सूत्रों ने बताया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद इन तीनों मामलों में वाड्रा पर एक साथ आरोप तय होने का रास्ता साफ हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इन तीन मामलों में पहला मामला गुरुग्राम की जमीन खरीद से जुड़ा है, जहां

वाड्रा पर 7.5 करोड़ रुपये में जमीन खरीदकर कुछ ही महीनों में उसे 58 करोड़ रुपये में बेचने का आरोप है। दूसरा मामला भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े लंदन स्थित प्रॉपर्टीज का है, जिन्हें कथित तौर पर रक्षा सौदों से मिले अवैध पैसे से खरीदा गया था।

### संजय भंडारी और बीकानेर भूमि सौदा

वाड्रा पर दूसरा आरोप यूके स्थित हथियार डीलर संजय भंडारी के साथ कथित संबंधों का है। ईडी पहले ही संजय भंडारी और वाड्रा के करीबी सीसी थंपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जांच एजेंसी के अनुसार, भारत द्वारा स्विस कंपनी पिलाटस से 75 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए हुई डील में 310 करोड़ रुपये की कथित घूस दुबई स्थित भंडारी की कंपनी ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस एफजेडसी के खातों में गई।

# महाराष्ट्र में नॉनवेज खाने पर भिड़ गए गुजराती और मराठी

### 'गंदा' कहने को लेकर भड़के एमएनएस नेता,जमकर बवाल

**मुंबई (एजेंसी)।** महाराष्ट्र में भाषा को लेकर लंबे समय से विवाद होता रहा है। हाल ही में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने मराठी भाषा के लिए आंदोलन चलाने का आह्वान कर दिया था। कई जगहों पर ज्यादती की खबरों के बाद उन्होंने खुद ही आंदोलन वापस लेने की अपील भी की। अब मुंबई की ही एक सोसाइटी में मराठी और गुजराती समुदायों में खाने-पीने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि गुजराती

परिवार ने एक मराठी परिवार को गंदा कह दिया था। जानकारी के मुताबिक नॉनवेज खाने की वजह से गुजराती परिवार ने इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की। घटना घाटकोपर की संभव दर्शन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की है। परिवार का कहना है कि उनके नॉनवेज खाने को लेकर पड़ोसी ने आपत्ति जताई और अभद्र टिप्पणी की।

### संकट मोचन संगीत समारोह

राजेन्द्र शर्मा

(कला समीक्षक एवं उप सरकार में अधिकारी)


# 'सारंगी को बचाना है तो सारंगी की गर्द झाड़कर उसे बैठकों तक लाना होगा

भारतीय शास्त्रीय संगीत की परम्परा में सारंगी वाद्य पर पुरुष कलाकारों का आधिपत्य रहा है, इसे सबसे पहले बीती सदी के सातवें दशक में ख्यात सारंगी वादक पंडित राम नारायण की पुत्री अरुणा कल्हेत ने तोड़ा था। अरुणा कल्हे बीते लगभग चार दशकों से कनाडा जा बसीं।

इस रिक्तोता को समाप्त करने का बीड़ा जमशेदपुर (झारखंड) निवासी गौरी बनर्जी सती ने उठाया और आज युवा गौरी बनर्जी सती का नाम देश भर में देश की दूसरी महिला सारंगी वादक के रुप में जाना जाता है । वो पिछले साल भी इस समारोह में आई थीं। तब उन्होंने समारोह की छह निशाओं में नौ कलाकारों विदुषी कंकणा बनर्जी, नंदिनी बेडेकर, मीनाक्षी मजूमदार, दिवाकर कश्य्प, पंडित सौनक अभिषेकी, पंडित जयतीर्थ मेचुंडी, पंडित नीरज पारिख के साथ प्रभावशाली संगत की। संकट मोचन संगीत समारोह के 102वें आयोजन में दूसरी हाजिरी लगाने गौरी बनर्जी सती वाराणसी आई हुई हैं और इस बार पंडित अजय पोहनकर (मुंबई),रोहित पवार (दिल्ली), श्रीमती सोहनी राय चौधरी (कलकत्ता) पंडित नीरज पारीख (अहमदाबाद) के साथ समारोह की प्रथम व द्वितीय निशा में प्रस्तुतति दे चुकी हैं। गौरी चौथी निशा (19 अप्रैल) को विदुषी कंकना बनर्जी के साथ संगत करेंगी।

जमशेदपुर के साकची स्थित पेनार रोड के टाटा स्टील कंपनी के क्वार्टर में रहने वाले ख्यात तबला वादक पं. किशोर बनर्जी और उनकी सितार वादक पत्नीक तंद्रा बनर्जी के घर आंगन में जन्मीत गौरी को शास्त्रीय संगीत घुटटी में मिला है। इस मायने में वह अपने परिवार की चौथी पीढी की कलाकार हैं। छोटी बच्चीर गौरी सुबह शाम अपने पिता पं. किशोर बनर्जी को तबले पर और मां तंद्रा को सितार पर रियाज करते इन वाद्यों के प्रति आकर्षित हुई किन्तुर सितार वादक उनकी मां श्रीमती तंद्रा बनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स वाद्य यंत्रों की बढ़ती मांग और सारंगी की उपेक्षा से चिंतित थी। अपनी इस चिंता का हरण तंद्रा बनर्जी ने पांच बरस की अपनी बेटी गौरी के नन्हे हाथों में गज (सारंगी के तारों को रगड़ देने वाला उपकरण) पकड़वा कर तारों को छेड़ना सिखाया।

गौरी बनर्जी

घर पर ही अभ्यास करते करते गौरी सारंगी में खोई रहती। सारंगी हाथ में पकड़ जब घर से बाहर निकली तो 'एश मेये जनों कथा नेई' (यह सब लड़कियों के बूते का नहीं) जैसे तानों ने गौरी को सारंगी के प्रति प्रतिबद्धता से भर दिया।और गौरी ने ठान लिया कि वह जीवन में और कुछ बने न बने, लेकिन सारंगी वादक जरुर बनेगी।

गौरी बनर्जी की इस प्रतिबद्धता को परवान बनारस से निकलकर रांची जा बसे गुणी सारंगी वादक पं. काशीनाथ मिश्र व दिल्ली के दिग्गज उस्ताद साबरी खां साहब ने चढ़ाया। सारंगी के प्रति अपने प्रेम को बताते हुए गौरी कहती है कि 'सारंगी को बचाना है तो ऐसे ही जतन केसाथ संगीत से जुड़े घरानों को घरों के कोने में पड़ी धूल फांक रही सारंगी की गर्द झाड़कर उसे बैठकों तक लाना होगा। 'ए' ग्रेड आर्टिस्टस के रुप मे स्थातपित गौरी बनर्जी दूरदर्शन व आकाशवाणी के पांच दर्जन से अधिक राष्ट्रीय संगीत समारोहों, इंदौर के प्रतिष्ठापरक संगीत उत्सव राग आमिर, उदयपुर के महाराणा संगीत कुंभ, कालिदास समारोह (गुजरात) में अपनी प्रस्तुति दे चुकी है। गौरी बनर्जी की सारंगी के प्रति बेपनाह मोहब्बरत का नतीजा साल 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के समय सामने आया। जब गौरी बनर्जी को राजधानी दिल्ली के हैदराबाद हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप व मोदी के समक्ष सारंगी वादन का मौका मिला। गौरी की सारंगी प्रस्तुसति के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेसाख्ता कह उठे 'इंट्रस फंटास्टिक, इट्स वेलडन।' गौरी के सारंगी वादन से मंत्रमुग्ध ट्रंप ने गौरी के साथ सेल्फी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गौरी के वादन की भूरि भूरि प्रशंसा की ।

गौरी बनर्जी सती ने सारंगी के साथ साथ अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यानन दिया। वे फलस्वरुप चार्टर्ड एकांउटेंट हैं और हल्वौरनी के मूल निवासी उनके जीवन साथी पारितोष सती भी चार्टर्ड एकांउटेंट हैं। गौरी को सबसे अधिक संतोष और खुशी अपने पिता पं. किशोर बनर्जी के साथ संगत करने में मिलती है। बाप-बेटी की इस जोड़ी नेकई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नायाब युगलबंदी से सबको मोहित किया है। सफर के दौरान सारंगी को अपने गोद में लेकर बैठना उनका शगल है। वह कहती है कि सारंगी को इतना सम्माहन क्यों न दूं आखिर सारंगी से ही तो मेरी पहचान है। मैं अपने माता पिता के समान सारंगी का भी सम्माकन करती हूं ।

वर्तमान में सारंगी की उपेक्षा से दुखी गौरी बनर्जी सती कहती है कि 'आज अस्तित्व के संकट से गुजर रहा सबसे सुरीला बाजा सारंगी नई पौध को बड़ी उम्मीद से आवाज दे रहा है। देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं मगर ग्लैमर और पैसे की अंधी दौड़ ने राहें बदल दी हैं। इसमें पहल संगीत घरानों की ओर से होनी चाहिए, अन्य विधाओं से कोई होड़ नहीं किंतु सारंगी कहीं खूंटी पर न लटक जाए इसकी चिंता इन घरानों की जिम्मेदारी है।' उम्मीद की जानी चाहिए कि सारंगी वादक गौरी बनर्जी सती की आवाज संगीत घरानों तक पहुंचेगी ।

## कार से 7 लाख रुपए चोरी

### मंडी से आलू बेचकर लौटे थे किसान, सिख मोहल्ले में पार्किंग से उड़ाया बैग

**इंदौर (एजेंसी)।** इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र के सिख मोहल्ला इलाके में सोमवार शाम शाजापुर से आए किसानों के साथ चोरी की वारदात हो गई। किसान चोइथराम मंडी से आलू का पेमेंट लेकर लौट रहे थे। उन्होंने कार सड़क किनारे पार्क की और पास की दुकान से सामान लेने चले गए। जब लौटे तो कार से 7 लाख रुपए से भरा बैग गायब मिला। शाजापुर निवासी गोविंद पाटीदार और प्रवीण पाटीदार ने एमजी रोड थाने पर एफआईआर दर्ज करवाई है। शिकायत के अनुसार, दोनों किसान आलू बेचने चोइथराम मंडी आए थे। मंडी से पेमेंट मिलने के बाद उन्होंने रकम एक बैग में रखी और सिख मोहल्ला स्थित कुंदन ट्रेडर्स पर कुछ सामान खरीदने पहुंचे। इसी दौरान एक ठेले वाले ने उन्हें सूचना दी कि उनकी कार से आम नीचे गिरे पड़े हैं। जब वे कार के पास पहुंचे तो गेट खुला मिला और ज़मीन पर कुछ आम पड़े थे। कार की तलाशी ली तो पता चला कि सीट पर रखा बैग गायब है। उन्होंने आसपास के इलाके में बैग तलाशा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आसपास के दुकानदारों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद किसान थाने पहुंचे और चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

## तेज धूप के बीच छाए बादल

### देर रात कई इलाकों में बूंदाबांदी ; गर्मी से राहत नहीं

**इंदौर (एजेंसी)।** इंदौर में अप्रैल के दो हफ्तों में 6 दिन ऐसे रहे जब दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। अभी भी मौसम के तेवर तीखे बने हुए हैं। गुरुवार को भी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। शाम को तेज हवाएं चलीं और बादल छा गए। इसके बाद रात में कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। शुक्रवार सुबह से ही तेज धूप के साथ बीच-बीच में बादल छा रहे हैं। इसके बावजूद गर्मी का असर बना हुआ है। गुरुवार को दिन का तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक था। रात को बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन गर्मी में कोई खास कमी नहीं आई। रात का न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक था। मौजूदा मौसम के बदलाव का असर अगले तीन-चार दिनों तक गर्मी के रूप में ही देखने को मिलेगा। खासकर राजस्थान से सटे जिलों में गर्मी का असर ज्यादा रहेगा। इंदौर में भी फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इंदौर की रातें भी अब काफी गर्म हो गई हैं। पिछले चार दिनों से रात का तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। इससे रात में कूलर और एसी का उपयोग बढ़ गया है। अब अप्रैल के तीसरे हफ्ते में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के जोर पकड़ने के साथ, इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में रात का तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक वी. एस. यादव के अनुसार, दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही रात की गर्मी भी बढ़ रही है। अगले 5 दिन तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। हालांकि, फिलहाल लू का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

## नशे में धुत युवक ने चार गाड़ियों को मारी टक्कर

### गर्भवती महिला कार भी चपेट में, घायल ड्राइवर को कराया भर्ती, कार जब्त

**इंदौर (एजेंसी)।** इंदौर में गुरुवार देर रात शहर के पलासिया क्षेत्र में एक तेज़ रफ्तार कार ने बेकाबू होकर एक के बाद एक चार वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में कार चालक भी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए एमवाय अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने आरोपी युवक की कार जब्त कर ली है, हालांकि अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पलासिया पुलिस के अनुसार, कार को शुभम चौरसिया नाम का युवक चला रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वह नशे की हालत में था। पहले उसने एक कार को टक्कर मारी, फिर एक पैसेंजर ऑटो रिक्शा और एक बाइक को भी चपेट में ले लिया। हादसे के दौरान एक कार में गर्भवती महिला सवार थी, जिसे परिजन इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे। टक्कर के बाद वे तुरंत महिला को लेकर रवाना हो गए और घटनास्थल पर नहीं रुके। इधर, शुभम चौरसिया भी अपनी कार में घायल हो गया था। राहगीरों की मदद से उसे बाहर निकाला गया और एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए। देर रात पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार जब्त कर ली है और पूरे मामले की जांच जारी है।

# इंदौर में 60 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल तैयार

**मांगलिया में बने नए भवन का मई में सीएम करेंगे शुभारंभ, मंत्री सिलावट ने किया दौरा**

**इंदौर (एजेंसी)।** इंदौर के सबसे बड़े 60 बिस्तरों वाले सरकारी आयुष (आयुर्वेद) अस्पताल का नया भवन लगभग तैयार हो गया है। साज-सज्जा और मॉडर्न सुविधायुक्त इस नए भवन का शुभारंभ मई में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और इंदर सिंह परमार की उपस्थिति में होगा। मांगलिया में लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बने भवन का गुरुवार को जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने निरीक्षण किया। इस भवन का सिविल वर्क पूर्ण हो गया है। अब केवल चिकित्सकीय सुविधाएं और उपकरण स्थापित करने का काम बाकी है। यह भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। मंत्री सिलावट ने अधिकारियों से कहा कि यह मानव सेवा और स्वास्थ्य का एक बड़ा केंद्र है। हमारा फर्ज है कि इस स्थान की महत्ता को देखते हुए इसके रखरखाव पर विशेष ध्यान दें। जनभागीदारी से सुविधाओं का विस्तार करें। उन्होंने आयुष विभाग के डॉक्टरों और स्टाफ से कहा कि अस्पताल में जो भी सुविधाएं बढ़ाना होंगी उसके लिए राज्य शासन द्वारा सभी संभव प्रयास किए जाएंगे।

**अस्पताल में मिलेंगी ये सुविधाएं-** अस्पताल में उपचार की सभी आधुनिक सुविधाएं रहेंगी। पंचकर्म तथा योग से भी उपचार किया जाएगा। डिलीवरी की सुविधा भी होगी। अस्पताल में सोनोग्राफी, पेथोलॉजी, एक्स-रे आदि जांच सुविधाएं भी रहेंगी।

### मंत्री सिलावट ने दिए यह निर्देश

अस्पताल का स्टाफ बढ़ाने, नए कामों के लिए प्रस्ताव बनाने का निर्देश। अस्पताल परिसर में बगीचा विकसित करने। समीप के नाले के सौंदर्यीकरण का निर्देश। सीटी स्कैन मशीन भी लगाने के निर्देश। अस्पताल में 10 एसी लगाने और एक एम्बुलेंस देने की घोषणा भी की।

### प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डकाच्या का किया निरीक्षण

मंत्री सिलावट ने सांवेर क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डकाच्या का भी निरीक्षण किया। स्वास्थ्य केन्द्र में लैब, मेल वार्ड, फीमेल वार्ड, लेबर रूम, माइनर ओटी/ड्रेसिंग, इंजेक्शन रूम, रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड रूम, मेडिकल ऑफिसर रूम, ऑफिस रूम, जनरल स्टोर, कोल्ड चैन, पीने के पानी की सुविधा, वेटिंग एरिया आदि के काम किए जाएंगे।

# आईटी कॉन्क्लेव से पहले सीएम का हैदराबाद दौरा संभव

### निवेशकों से करेंगे मुलाकात ; इंदौर कॉन्क्लेव में चार नीतियां होंगी लॉन्च

**इंदौर (एजेंसी)।** इंदौर में 27 अप्रैल को 'एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025' के नाम से आयोजित होने वाले आईटी कॉन्क्लेव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इस कॉन्क्लेव से पहले मुख्यमंत्री, सचिव और संबंधित विभागों के अधिकारी रोड शो के लिए हैदराबाद जा रहे हैं। एमपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी आईटी कॉन्क्लेव से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हैदराबाद रोड शो की तैयारियों में जुटे हैं। इस रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री आईटी सेक्टर, मेडिकल डिवाइस, फार्मा सेक्टर और फूड प्रोसेसिंग से संबंधित उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। एमपीईडीसी के अधिकारियों के अनुसार, इंदौर में होने जा रहे इस आईटी कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री आईटी सेक्टर से संबंधित नई पॉलिसी की घोषणा करेंगे। यह नीति इंदौर सहित मध्य प्रदेश को देश और दुनिया की आईटी कंपनियों के लिए एक प्रमुख केंद्र बना देगी। कॉन्क्लेव में

राज्य सरकार की 'ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति', 'सेमी-कंडक्टर नीति', 'ड्रोन नीति' और 'एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (एवीजीसी-एक्सआर) नीति' के क्रियान्वयन के लिए गाइडलाइन्स भी जारी की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य है कि ये गाइडलाइन्स निवेशकों और सरकार के बीच एक पारदर्शी सेतु सिद्ध हों।

**नीतियां होंगी लॉन्च-** ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) नीति, मध्य प्रदेश को डेटा एनालिसिस, साइबर सुरक्षा, अनुपालन, एआई रिसर्च और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक कंपनियों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने हेतु निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नीति के तहत लेवल-1 और एडवांस्ड जीसीसी के लिए पूंजी निवेश प्रोत्साहन, वेतन सब्सिडी, किराया प्रतिपूर्ति और ब्याज सहायता जैसे प्रावधान होंगे।

**सेमी-कंडक्टर नीति-** फेबलेस कंपनियों और विनिर्माण इकाइयों दोनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें डिज़ाइन प्रतिपूर्ति, आधारभूत संरचना सहायता, ईपीएफ प्रोत्साहन और चिप टेप-आउट अनुदान शामिल हैं। यह नीति विशेष रूप से भारत सरकार की डीएलआई योजना में सम्मिलित द्वितीय श्रेणी की कंपनियों को समान अवसर देने हेतु तैयार की गई है। बड़े प्रस्तावों की त्वरित स्वीकृति के लिए कैबिनेट समिति को अधिकृत किया गया है।

**मेयर इन काउंसिल की बैठक**

## इंदौर के विकास की नई योजनाएं होंगी पास, जल प्रदाय समेत 21 प्रस्तावों पर होगी बात

**इंदौर (एजेंसी)।** मेयर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में 18 अप्रैल को महापौर सभा कक्ष में मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में निगम आयुक्त, सभी एमआईसी सदस्य और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। बैठक में कुल 21 मुद्दे रखे।

**ये रहेंगे वे मुद्दे, जिन पर निर्णय लिया जाएगा-** जोन 12 के वार्ड 65 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर की तीन गलियों और मेन रोड को जनसहयोग से सीमेंट कांक्रीट करने के लिए रू. 8.34 करोड़ की स्वीकृति। चंदन नगर चौराहा से नगीन नगर होते हुए नंदन नगर तक की लिंक रोड को इंदौर विकास योजना में शामिल करने हेतु भूमि उपांतरण और जनरेटिंग एरिया घोषित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

चंदन नगर चौराहा से नंदन नगर, कालानी नगर होते हुए एयरपोर्ट रोड तक लिंक रोड निर्माण के अंतर्गत सीमेंट कांक्रीट, पुल-पुलिया निर्माण, फुटपाथ, स्टॉर्म वॉटर लाइन, विद्युत लाइन शिफ्टिंग आदि कार्यों के लिए 25.62 करोड़ के टेंडर को मंजूरी। कबीटखेड़ी स्थित 245 एमएलडी प्लांट से रेवती रेंज वृक्षारोपण स्थल तक रीयूज़्ड वॉटर लाइन बिछाने हेतु टेंडर दरों को स्वीकृति। हाइड्रेंट निर्माण कार्य के लिए सात दिन की अल्प अवधि वाले टेंडर से एजेंसी नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव। जलप्रदाय से संबंधित संचालन, संधारण एवं निर्माण कार्यों के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने हेतु स्वीकृति। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित पैकेज-3 और पैकेज-4 की 964.60 करोड़ लागत की स्वीकृति और टेंडर आमंत्रण संबंधी प्रस्ताव। 2025-26 के लिए जोन 1 से 22 के अंतर्गत ट्यूबवेल, हैंडपंप, डगवेल, संपवेल, हाइड्रेंट, फव्वारों से संबंधित जलप्रदाय के इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एवं अन्य कार्यों हेतु वार्षिक संधारण कार्य की तकनीकी, प्रशासकीय, वित्तीय स्वीकृति एवं टेंडर की अनुमति। फायर प्रकोष्ठ के गठन के लिए फायर अमले के पदों की पूर्ति संबंधी प्रस्ताव। जल उपभोक्ता प्रभार की दरों का युक्तिकरण और बिलिंग प्रक्रिया का मानकीकरण किए जाने का मुद्दा। नागरिक पत्रिका के प्रकाशन के लिए प्राप्त टेंडर दरों की स्वीकृति। शहर के 41 आदर्श यूरिनल्स के संचालन और संधारण से संबंधित प्रस्ताव। इंदौर स्थित स्वामी प्रीतमदास गोविंदराम पारमार्थिक संस्थान द्वारा निर्मित, संचालित और संधारित स्वामी प्रीतमदास सभागृह को लीज पर देने के संबंध में आयुक्त का पत्र। स्कीम 140 में स्थित अग्रवाल पब्लिक स्कूल चौराहे का नामकरण संबंधी प्रस्ताव। स्कीम 140, जोन 19 के सामने स्थित उद्यान का नामकरण संबंधी प्रस्ताव।

## भगवान महाकाल का चंद्र, त्रिनेत्र और त्रिपुण्ड के साथ रजत मुकुट अर्पित कर श्रृंगार

**उज्जैन (एजेंसी)।** विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में शुक्रवार तड़के भस्म आरती के दौरान मंदिर के कपाट खोले गए। सबसे पहले सभा मंडप में वीरभद्र जी के कान में स्वस्ति वाचन कर घंटी बजाकर भगवान से आज्ञा लेकर सभा मंडप वाले चांदी के पट खोला गया। गर्भगृह के पट खोलकर पुजारी भगवान का श्रृंगार उतार कर पंचामृत पूजन के बाद कर्पूर आरती की। नंदी हाल में नंदी जी का स्नान,ध्यान, पूजन किया गया। जल से भगवान महाकाल का अभिषेक करने के पश्चात दूध,दही,घी,शक्कर शहद फलों के रस से बने पंचामृत से पूजन किया गया। भगवान महाकाल को रजत चंद्र त्रिनेत्र और त्रिपुण्ड के साथ रजत मुकुट अर्पित कर श्रृंगार किया,भांग चन्दन ड्रायफ्रूट और भस्म चढ़ाई गई, शेषनाग का रजत मुकुट रजत की मुण्डमाल और रुद्राक्ष की माला के साथ-साथ सुगन्धित पुष्प से बनी फूलों की माला धारण की भगवान महाकाल ने फल और मिष्ठान का भोग लगाया।

# इंदौर के भिक्षुक पुनर्वास केंद्र का पेमेंट अटका

**संभागायुक्त से मिली संचालिका, बोली-104 कर्मचारियों के जीवन का सवाल है**

**इंदौर (एजेंसी)।** शहर को भिक्षुक मुक्त बनाने में सराहनीय काम करने वाली भिक्षुक पुनर्वास केंद्र की संचालिका रूपाली जैन कर्मचारियों व अन्य पेमेंट के लिए परेशान है। मंगलवार को जनसुनवाई में शिकायत करने के बाद भी अभी तक नगर निगम में अटका पेमेंट नहीं मिला है। इसके बाद उन्होंने संभागायुक्त दीपक सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया था। गुरुवार को वह दोबारा उनसे मिलने पहुंची और उनके नाम का भी ज्ञापन दिया। उन्होंने संभागायुक्त को कहा कि यह सिर्फ पेमेंट का मामला नहीं है बल्कि केंद्र के 104 कर्मचारियों के जीवन का सवाल है। रूपाली जैन ने बताया कि केंद्र में कई कर्मचारियों ने दिन-रात मेहनत कर अभियान को सफल बनाया है। इतनी मेहनत करने के बाद भी ये परेशानी उठाना पड़ रही है।

### दिल्ली से भी आ चुका है कॉल

रूपाली जैन ने बताया कि इस मामले की जानकारी दिल्ली भी पहुंच चुकी है। दिल्ली से सामाजिक न्याय मंत्रालय से नेशनल कोऑर्डिनेटर का भी कॉल आया था। उन्होंने भी पेमेंट नहीं मिलने की जानकारी ली है। बातचीत में उन्होंने कहा है कई बार पत्र लिखा

जा चुका है। अधिकारियों से वीसी में कहा जा चुका है कि ये भुगतान भारत सरकार का है, इसे रोका नहीं जा सकता। ये आपको इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को देना होगा। रूपाली जैन ने बताया कि नेशनल कोऑर्डिनेटर को भी ये जानकार आश्चर्य हुआ कि अभी तक पेमेंट नहीं मिला है।

### संभागायुक्त से फिर मिलेंगी रूपाली जैन

रूपाली जैन ने कहा है कि इस मामले में वे एक बार फिर संभागायुक्त दीपक सिंह से मिलेंगी। इस मामले में आगे क्या कुछ किया जाना है फिलहाल उसकी रणनीति तैयार नहीं हुई है। जल्द ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि जैन का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो पेमेंट बचा हुआ है वह उन्हें मिल जाएगा।

### ये है पूरा मामला

दरअसल, बीते मंगलवार को नगर निगम की जनसुनवाई में भिक्षुक पुनर्वास केंद्र का मामला गरमा गया था। पेमेंट की शिकायत लेकर संचालिका रूपाली जैन ने निगमायुक्त शिवम वर्मा से सवाल कर दिए थे। मामला इतना बढ़ा कि निगमायुक्त ने संचालिका से कह दिया था कि आप पांच मिनट में मुझे दस्तावेज पेश कीजिए आप सही होंगी तो आज ही उनका पेमेंट कराएंगे और संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई करेंगे। इस पर संचालिका ने वहां दस्तावेज भी पेश कर दिए।

# इंदौर के महू तहसील की 18 गांवों को मिलेगा मुआवजा

**इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन भूमि अधिग्रहण के लिए मिले 267 करोड़ रुपए**

**इंदौर (एजेंसी)।** इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट की निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे की जा रही है। इस परियोजना के लिए इस बार बजट में 267.50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि से प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। मप्र के तीन जिलों के 77 गांव से होकर रेल लाइन गुजरेगी। नवंबर-2024 में रेल मंत्रालय ने इन 77 गांव की जमीन अधिग्रहण करने के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। इसी वर्ष मंत्रालय ने इंदौर जिले की महू तहसील के 18 गांवों की सूची जारी की थी। नई रेल लाइन धार, खरगोन और बड़वानी जिलों के आदिवासी अंचल के लिहाज से महत्वपूर्ण है। परियोजना से लगभग एक हजार गांव और 30 लाख आबादी का रेल सेवाओं से सीधा संपर्क होगा। अनुमान के मुताबिक प्रोजेक्ट पूरा होने पर 16 जोड़ी से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनों का संचालन होगा, जिनमें 50 लाख यात्री शुरुआती वर्षों में सफर करेंगे। हर साल इस प्रोजेक्ट से रेलवे को 900 करोड़ से अधिक का राजस्व मिलेगा। इंदौर से मुंबई की दूरी भी 830 किमी से घटकर 568 किमी रह जाएगी। अफसरों के अनुसार रेल मंत्रालय द्वारा 14 जनवरी को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार महू तहसील के खेड़ी, चैनपुरा, कमदपुर, खुदालपुरा, कुराड़ाखेड़ी, अहिल्यापुर, नांदेड़, जामली, कैलोद, बेरछा, गवली पलासिया, आशापुरा, मलेंडी, कोदरिया, बोरखेड़ी, चौरड़िया, न्यू गुराडिया, और महू केंटोमेंट एरिया की चिह्नित जमीन का रेल प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण होना है।

**309 किलोमीटर लंबी लाइन से 30 लाख की आबादी को फायदा-** इंदौर-मनमाड़ रेल प्रोजेक्ट के तहत कुल 309 किलोमीटर लंबी रेल लाइन इंदौर से महाराष्ट्र के मनमाड़ तक बिछाई जाएगी। इस परियोजना से लगभग एक हजार गांवों और

30 लाख की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। रेलवे ने भू-स्वामियों को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। प्रोजेक्ट के पूरा होने पर 16 जोड़ी यात्री ट्रेनों का संचालन होगा, और शुरुआती वर्षों में 50 लाख यात्रियों के सफर करने का अनुमान है। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में 170 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जाएगी, जिसमें 18 स्टेशन शामिल होंगे।

**इंदौर से मुंबई की दूरी 830 किमी से घटकर 568 होगी-** इंदौर-मनमाड रेल प्रोजेक्ट के तहत धार, खरगोन और बड़वानी जिले के आदिवासी अंचल से पहली बार रेल लाइन गुजरेगी, जिससे इन क्षेत्रों को रेल सेवाओं से सीधा संपर्क मिलेगा। इस परियोजना से लगभग एक हजार गांव और 30 लाख आबादी को फायदा होगा। इंदौर से मुंबई की दूरी भी 830 किलोमीटर से घटकर 568 किलोमीटर रह जाएगी। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट बहुत प्रतीक्षित है और इसके लिए अब जमीन अधिग्रहण का काम तेजी से शुरू किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की है, और आगामी बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया जाएगा। प्रोजेक्ट पूरा होने पर 16 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का संचालन होगा, और शुरुआती वर्षों में 50 लाख यात्री सफर करेंगे। इस प्रोजेक्ट से रेलवे को हर साल 900 करोड़ से अधिक का राजस्व मिलेगा। इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन योजना की शुरुआत 1918 में होलकर काल में हुई थी। इस परियोजना को गति शक्ति योजना में शामिल किया गया है, जिसके तहत इसकी निगरानी सीधे पीएमओ से की जाएगी।

## संपादकीय

# हार्वर्ड विवि के साहस को सलाम!

अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित और पुराने हार्वर्ड विवि द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के आगे न झुकने और अपनी शैक्षणिक स्वतंत्रता कायम रखने का फैसला लेकर विवि ने समूचे शिक्षा जगत को सकारात्मक और ठोस संदेश दिया है। हार्वर्ड विवि के ये तेवर दुनिया में ज्ञान और शोध की पवित्रता तथा अपने काम और चिंतन की स्वतंत्रता को ही पुरिपुष्ट करते हैं। हार्वर्ड के इन तेवरों से भारत के विवि को भी काफी कुछ सीखने की जरूरत है, जहां ज्यादातर विवि अब सरकारी एजेंडा चलाने का माध्यम भर बन कर रह गए हैं। गुणवत्तापूर्ण शोध और ज्ञानार्जन अब कल की बात हो चुकी है। अमेरिका में हार्वर्ड विवि की स्थापना 1636 में तब हुई थी, जब अमेरिका ने ब्रिटेन से आजादी भी हासिल नहीं की थी। यह वो समय था जब भारत में मुगल बादशाह शाहजहां का शासन था और जो देश में ताजमहल जैसी अप्रतिम इमारतें तो बनवा रहा था, लेकिन देश में शिक्षा के अनूठे केन्द्र भी खुलें, इसका उसे कोई बोध नहीं था। हार्वर्ड न केवल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों में गिना जाता है बल्कि उसके पास सर्वाधिक सम्पत्ति भी है। शुरू में इसका सम्बंध चर्च से था। लेकिन बाद में यह धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का वैश्विक केन्द्र बन गया। इस विवि में 2100 से अधिक शिक्षक तथा 21 हजार से अधिक छात्र हैं, जिनमें एक तिहाई विदेशी छात्र होते हैं। हार्वर्ड में प्रवेश और वहां शिक्षा पाना अपने आप में गौरव की बात है। विवि अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के उसके अपने मूल्य हैं जैसे कि अकादमिक स्वतंत्रता, बौद्धिक खोज, चुनौतियों का सामना, सामाजिक दायित्व, गहन अध्ययन, आदि। इस विवि से कई विख्यात हस्तियां निकली हैं। हाल में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के शैक्षणिक संस्थानों को इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों के कारण संघीय वित्त पोषण में कटौती की धमकी दी है। इनमें हार्वर्ड विवि भी शामिल है। इस विवि में पिछले साल फिलीस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन हुए थे, जो राष्ट्रपति ट्रंप को नागवार गुजरे थे। अमेरिकी सरकार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 2.2 अरब डॉलर (लगभग 18.8 हजार करोड़ रुपये) के ग्रांट्स और कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज यानी रोक दिए हैं। साथ ही विवि को टैक्स छूट भी नहीं मिलेगी। इसके पूर्व ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड को एक चिट्ठी भेजी थी, जिसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटी मेरिट-बेस्ड एडमिशन और नौकरी देने की प्रक्रिया को अपनाए। यूनिवर्सिटी से ये भी कहा गया कि छात्रों और टीचर्स के बीच विविधता को लेकर जांच करवाई जाए। हार्वर्ड उन स्टूडेंट ग्रुप्स को फंड करना बंद करे, जो आपराधिक गतिविधियों, अवैध हिंसा या उत्पीड़न में शामिल हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी को प्रदर्शनों के दौरान फेस मास्क पहनने पर भी रोक लगाई जाए। लेकिन यूनिवर्सिटी ने अपनी नीतियां बदलने से इनकार कर दिया। हार्वर्ड ने ट्रंप प्रशासन की मनमानी का मुखर विरोध करके जता दिया है कि वह ऐसा विवि है जो सामाजिक न्याय और समानता के लिए प्रतिबद्ध है। हार्वर्ड विवि के अध्यक्ष एलन गार्बर ने कहा कि किसी भी सरकार को- चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो- यह तय नहीं करना चाहिए कि निजी विश्वविद्यालय क्या पढ़ा सकते हैं, किसे प्रवेश दे सकते हैं और किसे काम पर रख सकते हैं, और अध्ययन और जांच के किन क्षेत्रों को आगे बढ़ा सकते हैं। हार्वर्ड ने जिन प्रस्तावों को अपनाने से इनकार किया है, उसमें एडमिशन, फैकल्टी की नियुक्ति, छात्रों के आंदोलन और विविधिता से जुड़े नियम शामिल हैं। हालांकि ट्रंप सरकार ने नियमों को नहीं मानने पर हार्वर्ड के अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों की भी फंडिंग रोकी है। कई अमेरिकी संस्थान भी इसी तरह के एक्शन का सामना कर रहे हैं।

## नजरिया

नृपेन्द्र अभिषेक नृप
लेखक स्तम्भकार हैं।

# शिक्षा बनाम सत्ता-हार्वर्ड की हुंकार

**अमेरिका की राजनीति और शिक्षा प्रणाली के बीच हमेशा एक जटिल रिश्ता रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल (2016-2020) में यह टकराव स्पष्ट और तीव्र रूप में सामने आया। इस टकराव का एक प्रतीकात्मक केंद्र बना - हार्वर्ड विश्वविद्यालय। एक ओर था शताब्दियों पुराना यह प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान, जो अकादमिक स्वतंत्रता, उदार विचार और बौद्धिक विविधता का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरी ओर था ट्रंप प्रशासन, जो राष्ट्रवादी राजनीति, संरक्षणवाद और वैचारिक आग्रहों के लिए जाना गया। यह संघर्ष केवल दो संस्थानों के बीच नहीं था, बल्कि यह उस गहराते विभाजन की कहानी है जो आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों को प्रभावित कर रहा है।**

शिक्षा केवल ज्ञान का विस्तार नहीं, बल्कि विचारों की आज़ादी और अभिव्यक्ति की निर्भीकता का आधार होती है। जब विचारधाराएँ सत्ता के गलियारों से निकलकर शिक्षण संस्थानों के प्रांगण में हस्तक्षेप करने लगें, तब यह केवल अकादमिक स्वतंत्रता का संकट नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर भी प्रहार होता है। अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ट्रंप प्रशासन के बीच उपजा टकराव इसी विमर्श की परिणति है- जहाँ एक ओर विश्वविद्यालय अपने बौद्धिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर अडिग खड़ा है, वहीं दूसरी ओर एक सत्ता प्रतिष्ठान है जो वैचारिक भिन्नता को सहन करने से इंकार करता है।

इस प्रकरण की जड़ें गहरी हैं। ट्रंप प्रशासन के दौरान हार्वर्ड ने आव्रजन, नस्लभेद, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 नीति जैसे कई मुद्दों पर मुखर विरोध दर्ज कराया। नतीजतन, प्रशासनिक दबाव, अनुदानों में कटौती, और राजनीतिक हमले तेज़ होते गए। हार्वर्ड ने इसे अकादमिक स्वतंत्रता पर हमला माना और न्यायपालिका का रुख किया। इस संघर्ष में केवल एक विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं थी, बल्कि यह सवाल भी था कि क्या शिक्षा की दुनिया राजनीति के हस्तक्षेप से बच पाएगी?

अमेरिका की राजनीति और शिक्षा प्रणाली के बीच हमेशा एक जटिल रिश्ता रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल (2016-2020) में यह टकराव स्पष्ट और तीव्र रूप में सामने आया। इस टकराव का एक प्रतीकात्मक केंद्र बना - हार्वर्ड विश्वविद्यालय। एक ओर था शताब्दियों पुराना यह प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान, जो अकादमिक स्वतंत्रता, उदार विचार और बौद्धिक विविधता का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरी ओर था ट्रंप प्रशासन, जो राष्ट्रवादी राजनीति, संरक्षणवाद और वैचारिक आग्रहों के लिए जाना गया। यह संघर्ष केवल दो संस्थानों के बीच नहीं था, बल्कि यह उस गहराते विभाजन की कहानी है जो आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों को प्रभावित कर रहा है।

### टकराव की पृष्ठभूमि: आदर्शों की लड़ाई

हार्वर्ड विश्वविद्यालय लंबे समय से प्रगतिशील और समावेशी मूल्यों का पोषक रहा है। विविधता, आप्रवासन, पर्यावरण संरक्षण और नस्लीय न्याय जैसे मुद्दों पर इसकी नीतियाँ अकसर रिपब्लिकन नीतियों के विपरीत जाती रही हैं। ट्रंप प्रशासन की ' America First ' नीति, शरणार्थियों पर प्रतिबंध, मुस्लिम देशों से यात्रा निषेध, और DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) जैसे कार्यक्रमों को समाप्त करने की कोशिशों के विरुद्ध हार्वर्ड लगातार मुखर रहा।

इस विरोध की परिणति कई कानूनी लड़ाइयों में हुई। हार्वर्ड ने ड्रीमर्स के हक़ में अदालत में मुकदमे दायर किए। 2020 में, जब ट्रंप प्रशासन ने एक नीति लाई जिसके तहत यदि विदेशी छात्र ऑनलाइन कक्षाएं ही ले रहे हों तो उन्हें अमेरिका में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो हार्वर्ड और MIT ने इस नीति के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और जीत हासिल की।

### ट्रंप प्रशासन की शैक्षिक नीति: एक वैचारिक ध्रुवीकरण

ट्रंप प्रशासन की उच्च शिक्षा नीति का केंद्र था 'देशभक्ति शिक्षा' को बढ़ावा देना और 'वामपंथी प्रचार' को रोकना। ट्रंप ने बार-बार विश्वविद्यालयों को 'उदारवाद का गढ़' कहकर उनकी आलोचना की, और फ्री स्पीच के नाम पर अक्सर घृणा और विभाजन को वैध ठहराने की कोशिश की। इस दौरान शिक्षा विभाग ने कई बार विश्वविद्यालयों के वित्तीय स्रोतों, खासकर विदेशी फंडिंग, पर प्रश्नचिह्न खड़े किए।

हार्वर्ड को चीन से वित्तीय सहयोग को लेकर जांच का सामना करना पड़ा। यह राजनीतिक दबाव न केवल संस्थानों की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, बल्कि छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक भय का वातावरण भी निर्मित करता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों में बाधाएँ, सामाजिक विज्ञानों में वैचारिक जांच, और विदेशी छात्रों को लेकर आशंकाओं ने अकादमिक दुनिया को अस्थिर कर दिया।

### हार्वर्ड की प्रतिरोधात्मक भूमिका

ट्रंप प्रशासन की इन नीतियों के खिलाफ हार्वर्ड ने केवल विरोध दर्ज नहीं किया, बल्कि उसे संस्थागत रणनीति में भी बदला। विश्वविद्यालय ने विविधता और समावेशिता को और सशक्त करने की दिशा में प्रयास किए। उदाहरणस्वरूप, हार्वर्ड ने अपने विभिन्न विभागों में नस्लीय न्याय के अध्ययन को प्राथमिकता दी, और अकादमिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाईं।

हार्वर्ड ने ट्रंप प्रशासन की विदेशी छात्र विरोधी नीति को चुनौती देते हुए अदालत में दलील दी कि इस तरह की नीतियाँ न केवल अमानवीय हैं, बल्कि अमेरिकी विश्वविद्यालयों की वैश्विक प्रतिष्ठा और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुँचाती हैं। इस मामले में ट्रंप प्रशासन को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। यह अकादमिक स्वतंत्रता की एक बड़ी जीत थी।

### प्रतीकात्मक नहीं, संरचनात्मक संघर्ष

यह संघर्ष केवल दो संस्थाओं का नहीं था; यह दो विचारधाराओं, दो दृष्टिकोणों, और दो अमेरिका का टकराव था। एक ओर वह अमेरिका जो वैश्विकता, विविधता और मुक्त चिंतन को महत्व देता है; दूसरी ओर वह जो राष्ट्रवाद, नियंत्रण और संदेह को प्रमुख मानता है। ट्रंप के दौर में शिक्षा को भी एक युद्धभूमि बना दिया गया, जहाँ ज्ञान की स्वतंत्रता और राजनीतिक नियंत्रण आमने-सामने थे। हार्वर्ड और अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों ने इस टकराव में संविधान, स्वतंत्रता और अकादमिक आदर्शों की रक्षा की। उन्होंने दिखाया कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना का प्रशिक्षण भी है।

### भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह संघर्ष

भारत जैसे देश, जहाँ शिक्षा व्यवस्था अकसर राजनीतिक हस्तक्षेपों से प्रभावित होती है, हार्वर्ड बनाम ट्रंप प्रशासन की यह गाथा एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह बताती है कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, उनकी बौद्धिक निर्भीकता, और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता कैसे सत्ता के दमनकारी रूझानों का मुकाबला कर सकती है। भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए यह प्रेरणास्पद है कि वे केवल शिक्षण संस्थान न बनें, बल्कि समाज के विवेक और नैतिकता के प्रहरी भी बनें। जब शिक्षण संस्थान सत्ताधारी शक्तियों के दबाव में आ जाते हैं, तो लोकतंत्र की आत्मा खोने लगती है।

### शिक्षा बनाम राजनीति की नई कसौटी

आज जब वैश्विक स्तर पर दक्षिणपंथी विचारधाराएँ पुनर्जीवित हो रही हैं, तब शिक्षा को राजनीति से बचाकर रखना एक चुनौती बन गया है। हार्वर्ड और अन्य विश्वविद्यालयों ने यह साबित किया कि शिक्षा केवल सत्ता के उपकरण नहीं बन सकती। यह ज्ञान, संवाद और आलोचना का क्षेत्र है और लोकतंत्र की रक्षा की पहली पंक्ति।

आगे के लिए यह जरूरी है कि सरकारें शिक्षा की स्वायत्तता को सम्मान दें, शोध की स्वतंत्रता को बाधित न करें, और अकादमिक संस्थानों को वैचारिक प्रयोगशाला न बनाएं। वहीं विश्वविद्यालयों को भी चाहिए कि वे केवल विरोध न करें, बल्कि समाज में समावेशिता, संवेदना और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता को मज़बूती से पोषित करें।

### जब शिक्षा बोलती है...

हार्वर्ड बनाम ट्रंप प्रशासन का यह अध्याय इस बात का प्रमाण है कि जब शिक्षा संस्थान अपने आदर्शों पर डटे रहते हैं, तो वे सत्ता से भी टकरा सकते हैं। यह संघर्ष इस बात का साक्षी है कि अकादमिक स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है ङ्क सत्य को खोजने, असहमति को पोषित करने, और लोकतंत्र को जीवित रखने की जिम्मेदारी। आज जब पूरी दुनिया 'सच' को 'राष्ट्रहित' से, 'असहमति' को 'देशद्रोह' से और 'स्वतंत्रता' को 'अराजकता' से भ्रमित करने पर तुली है, तब हार्वर्ड जैसी संस्थाओं की भूमिका और भी निर्णायक हो जाती है। शिक्षा का काम सत्ता के इशारे पर चलना नहीं, बल्कि सत्य के मार्ग पर टिके रहना है, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो।

## पर्यावरण

ध्रुव शुक्ल
लेखक साहित्यकार हैं।

# खेती में दलाली का परिणाम है पराली

हरित क्रांति के नाम पर भारत की खेती की ज़मीन को जोतने, बीज बोने और फ़सल काटने के लिए मशीनों के हवाले किया जाता रहा है। वैश्विक दलालों ने देश के पारंपरिक बीज बदल दिए। गोधन की नस्लें बदल दीं। हमारे किसान खेती को लोभ के धंधे में बदलने पर राज़ी होते गये। इस पाप में पिछले पचास साल से राजनीति और बाज़ार शामिल रहे हैं। देश के ज़मींदार किसानों ने इसे स्वीकार करके खूब कमाई की है और ज़मीनों में ज़हरीले खाद डालकर उन्हें बाँझ बनाने में भी कोई संकोच नहीं किया है। सरकारें रासायनिक खाद पर सब्सिडी के लिए खजाना खाली करती रहीं, आज भी कर रही हैं। अब पारंपरिक आर्गेनिक खेती का बड़े किसानों के साथ सौदा करके बाज़ार ही उसे लाभ के धंधे में बदल रहा है। आज भी छोटे किसानों के दुख किसी को नहीं दिख रहे। उन्हें दी जाने वाली ख़ैरात को सम्मान निधि ज़रूर कहा जा रहा है।

इससे पहले देश के किसान बैलों और हल का उपयोग जोतने-बोने में करते थे। गोधन से खूब गोबर खाद उपलब्ध होती थी जो खेतों को सहज ही उर्वर बनाये रखती थी। जब फ़सल पक जाती थी तो पूरे देश में गाँव-गाँव से अपने हँसिए लेकर फ़सल काटने वाले लाखों लोग खेतों में फैल जाते थे। हाथों में थमें हँसिए की ख़ासियत है कि वह गेंहूँ और दूसरी सभी फ़सलों को पक जाने के बाद जड़ के बहुत करीब से काटता है। ज़मीन पर बड़े डण्ठल छूटते ही नहीं और हज़ारों हाथों को काम भी मिलता है और खूब भूसा पैदा होता है जो अनेक पालतू-दुधारू पशुओं की भूख बुझाता है। आजकल बाज़ार ने पशु आहार को भी धंधा बना लिया है। जब मशीनें फ़सल काटती हैं तो बड़े-डण्ठल खेतों में छोड़ देती हैं। ये डण्ठल ही तो पराली हैं जिन्हें जलाकर ज़मीन अगली फ़सल के लिए तैयार करना पड़ती है।

पराली जलाने से ज़मीन की सतह पर रहकर उसे उर्वर बनाने वाले तत्व, कीड़े और बैक्टीरिया भी जलकर मर जाते हैं। इसीलिए ज़मीन ज़्यादा खाद-पानी माँगती है। कुल मिलाकर मशीनों से होने वाली फ़सल कटाई ही पराली के पाप की जड़ है। बड़े किसान आज भी खेतों पर हँसिए की वापसी का संकल्प लेकर हज़ारों हाथों को काम दे सकते हैं और पराली जलाकर प्रदूषण फैलाने के पाप से बच सकते हैं। फिर देश की राजधानी का दम भी घुटने से बच सकता है।

मुझे याद है कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन पर फ़सल काटने वाले लोग अपने हँसिए लेकर आते थे। वे खेतों के करीब ही डेरा डाल लेते। वहीं बैगन का भुरता और गक्कड़ बनाकर खाते। उनका पूरा परिवार ही फ़सल कटैया की भूमिका निभाकर रोजी कमाता था। खेत कटाई के समय गिर गयी गेंहूँ की बालें बीन लेता था। उनके हाथ और हँसिए उनके साल भर के भोजन का इंतज़ाम कर लेते थे। उन्हें सरकार के मुफ़्त अनाज के भरोसे नहीं रहना पड़ता था। काश हमारी सरकारें और किसान खेती और लोगों की भलाई के इस रास्ते पर फिर लौट सकें। हमारे खेतों को सदियों से लोकगीत और बैलों के गले में बँधी घण्टियों की आवाज़ ही अच्छी लगती रही है। वे मशीनों की खड़-खड़ सुनकर ऊब गये हैं। पराली के साथ खेतों की जलती हुई उर्वर माटी की पीड़ा को कोई समझ क्यों नहीं रहा?

# पतियों को मुफ्त की सलाह, दूर रहे ऐसे गानों से

## वक्रोक्ति

मुकेश नेमा
लेखक मप्र के प्रशासनिक अधिकारी हैं।

वो गाना सुना है न आपने। न कजरे की धार न कोई किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो। न सुना हो आपने तो अब सुनिए। साफ पता चल रहा है कि कोई सकपकाया पति अपनी पत्नी को ब्यूटी पार्लर जाने से रोकना चाहता है। सीन यह है कि पत्नी ब्यूटी पार्लर जाने की तैयारी मे है। पति का पर्स उसके हाथ मे है। महीने के आखरी दिन है। प्राइवेट सेक्टर मे सुबह नौ से छह की जॉब करता पति घुटनों पर है। और उसका रोम रोम चाहता है कि पत्नी ब्यूटी पार्लर जाने का मन बदल ले।

पत्नी यदि कुछ चाह ले और उसका पति उसे रोक ले ऐसा कभी कहाँ होता है? इस गाने वाला पति शायद ये बात नही जानता। वो यह नही जानता कि पत्नी यदि ब्यूटी पार्लर जाना चाहती है तो उसे रोका जाना नामुमकिन है। इतिहास गवाह है जब भी किसी नादान ने ऐसा करने की कोशिश की है मुँह की ही खाई है। शास्त्र कहते हैं ब्यूटी पार्लर जाती पत्नी और मंदिर जाने की इच्छुक माता बहनों को उनके मन की करने से रोकना गौ हत्या के बराबर का पाप है। और आप के रोकने से क्या होता है। उन्हें जाना होगा तो वो जरूर जाएगी। आपको तिरस्कार करने की निगाहों से देखेगी वो। जमाना आपको दुतकारेगा और जब तक आप खुद का बचाव करेंगे वो अपने मन की करके वापस आ चुकी होगी।

चूँकि इस गाने वाला पति कड़का होने के बावजूद खुद को समझदार समझता है। वो झूठी तारीफ़ों के पुल से वैतरणी पार करने की कोशिश मे है। वो अपनी पत्नी को यह समझाना चाहता है कि तुम पैदाइशी सुंदर हो। तुम सादी हो पर तुमसे खुशबू आती है और मैं इसी में मस्त हूँ। और तुम इससे ज्यादा सुंदर दिखोगी तो उसका ताप मैं सहन नही कर पाऊँगा। इसलिए तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाकर धन और समय नष्ट नही करना चाहिए।

बंदे के समझदार होने का तो पता नही पर वो अव्वल दर्जे का काइयाँ जरूर है। वो अपनी पत्नी को यह समझाने की चेष्टा कर रहा है कि तुम्हारा यौवन ही तुम्हारा श्रंगार है और यही तुम्हारा गहना है। ऐसे में तुम्हारा सजने संवरने या ज्वेलरी की शॉप जाने की इच्छा रखना व्यर्थ है। साफ साफ पता चल रहा है कि बंदा मक्कार है। कंजूस है। पैसे को दाँत से पकड़ता है। गरीब है। गरीबी रेखा के नीचे नही जाना चाहता इसलिए पत्नी को सादगी के फायदे समझा रहा है।

आपको क्या लगता है? ये बदनीयत पति अपनी चाल में कामयाब हो पाया होगा? मेरे ख्याल से हरगिज नही। उसे यह नही पता दुनिया की हर पत्नी अपने पति से ज्यादा समझदार होती है। पति की मंशा क्या है वो उसके मुँह खोलने के पहले ही ताड़ लेती है। दूसरी बात यह कि हर महिला यह बात जानती भी है और मानती भी है कि वो बेहद सुंदर है। हीरा है। इसके बावजूद वो ब्यूटी पार्लर जाती है और यह मान कर जाती है कि हीरे को तराशने के लिए जौहरी के पास जाना ही होता है। और फिर और सुंदर दिखना हर महिला का जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे उससे छीना नही जा सकता। ऐसे मे सारे पतियों को मेरी ये मुफ्त की सलाह है। दूर रहे ऐसे गानों से। ख्याली पकवान हैं इनसे आपका पेट नही भरेगा। जिस कवि ने यह काल्पनिक गीत रचा वो भी अपनी बीबी को मन की करने से रोक नहीं सका। इसे गाने वाले पंकज उधास की पत्नी हमेशा उनसे उदास रहीं। सच तो ये है कि यदि आपकी पत्नी ब्यूटी पार्लर जाना चाहती है। मोतियों का हार खरीदने की इच्छा है उसकी। तो ऐसा होकर रहेगा। आपकी औक़ात नही कि आप उसे रोक लें। ऐसे में हमे मान लेना चाहिए कि गाने सुनने गुनगुनाने मे भले अच्छे लगे पर ये किसी मतलब के नही है।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पी.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस प्रा. लि., राउखेड़ी, देवास रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 662, साईं कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक - उमेश त्रिवेदी
संपादक (म.प्र.) -विनोद तिवारी
कार्यकारी प्रधान संपादक - अजय बोकिल
स्थानीय संपादक - हेमंत पाल
प्रबंध संपादक - अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

## व्यंग्य

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त
लेखक व्यंग्यकार हैं।

# नेताजी की नाक और लोकतंत्र की राख

नेताजी की नाक केवल एक साधारण नाक नहीं थी, बल्कि इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने योग्य थी। गाँव के बुजुर्गों का कहना था कि जब नेताजी पहली बार चुनाव लड़े थे, तब उनकी नाक एकदम सामान्य थी—छोटी, संतुलित, और इंसानी सीमाओं के भीतर। लेकिन जैसे-जैसे उनके कार्यकाल बढ़ते गए, वैसे-वैसे उनकी नाक भी लंबी होती चली गई। यह कोई रहस्य नहीं था बल्कि उनकी राजनीतिक सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण था। इतिहासकारों ने तो यहाँ तक सिफारिश कर दी थी कि इस नाक को 'राष्ट्रीय धरोहर' घोषित कर देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ देख सकें कि कैसे राजनीति केवल विचारों से नहीं, बल्कि नाक की लंबाई से भी प्रभावित होती है।

जब किसी पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि 'नेताजी, आपकी नाक इतनी लंबी कैसे हो गई?' तो नेताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, 'जनता के प्यार से!' यह सुनकर जनता हैरान रह गई। कोई यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि असल में नेताजी की नाक उनके किए गए वादों की लंबाई से मेल खाती थी। जितने वादे, उतनी लंबी नाक! यह नाक एक जीवंत स्मारक बन चुकी थी, जो याद दिलाती थी कि राजनीति में अनुभव केवल काम करने से ही नहीं, बल्कि वादे करने और उन्हें तोड़ने से भी बढ़ता है।

नेताजी के पास हर समस्या का समाधान था—बस समस्या का नाम मत लीजिए! अगर किसी गाँव में पानी नहीं आ रहा तो नेताजी कहते, 'भाई, पानी नहीं आ रहा, इसका मतलब यह नहीं कि व्यवस्था खराब है। इसका मतलब यह है कि हमारे जल स्रोत सुरक्षित हैं। हम जल संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं।' बिजली नहीं आती तो उनका जवाब होता, 'सरकार जनता को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। मोमबत्ती जलाइए, बचपन की यादें ताजा कीजिए।' जब किसी ने उनसे पूछा कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, तो उनका जवाब था, 'हमने जनता को मजबूत बनाने का प्रण लिया है। बीमारियाँ खुद ही ठीक होने दें, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएँ।' इस तर्क में इतनी मजबूती थी कि विरोधियों को भी उनके तर्कशास्त्र के आगे झुकना पड़ता था।

चुनाव नजदीक आते ही नेताजी के भाषण और भी चमत्कारी हो जाते। एक दिन जब उन्होंने जनता को संबोधित किया तो बोले, 'हमने पाँच सालों में इतने विकास किए हैं कि अगर आप गिनने बैठें तो उंगलियाँ कम पड़ जाएँगी।' जनता ने सवाल किया, 'नेताजी, बताइए, कौन-कौन से विकास हुए?' नेताजी मुस्कुराए, चश्मा ठीक किया और बोले, 'पहला विकास - हमारी पार्टी मजबूत हुई। दूसरा - हमारा परिवार समृद्ध हुआ। तीसरा - हमारे करीबी ठेकेदारों की किस्मत चमकी। बाकी तो आप खुद समझदार हैं।' यह सुनकर जनता पहले तो हतप्रभ रह गई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि नेताजी के भाषणों में ऐसी जादुई ताकत थी कि वे बिना कोई ठोस जवाब दिए भी तालियाँ बजवा सकते थे।

सड़कें इतनी खराब थीं कि ऐसा लगता था जैसे किसी ने गड्ढों के ऊपर थोड़ा-बहुत सड़क डाल दी है। जब लोगों ने शिकायत की तो नेताजी बोले, 'देखिए, ये स्मार्ट गड्ढे हैं। इसमें पानी भर जाए तो कुआँ बन जाता है, सूख जाए तो स्टेडियम।' जनता इस चमत्कारी व्याख्या से चकरा गई। किसी ने मज़ाक में कह दिया, 'नेताजी, सड़कें तो आपकी नाक जितनी भी ठीक नहीं हैं।' नेताजी हँसते हुए बोले, 'सड़कें लंबी बनाने के लिए पहले वोट लंबी संख्या में चाहिए!'

सफाई व्यवस्था भी ऐसी थी कि कूड़ा सड़कों पर बिखरा हुआ था, लेकिन नेताजी की नजर में यह विकास का प्रतीक था। उनका कहना था, 'स्वच्छता अभियान के तहत हमने इतना कूड़ा जमा किया है कि अब बस उसे हटाने की औपचारिकता बची है। हमारी सरकार इसे ऐतिहासिक कूड़ा घोषित करवा सकती है!' जब किसी ने पूछा कि कूड़ा उठेगा कब, तो बोले, 'योजना बन रही है, अगले चुनाव तक सब साफ हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वोट बैंक गंदा नहीं होना चाहिए!'

फिर आया चुनाव परिणाम का दिन। नेताजी हार गए। हारने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बयान दिया, 'हमारी हार जनता की जीत है, और जनता की जीत आखिर हमारी ही जीत है। मतलब, हम हारे ही नहीं!' रिपोर्टर ने पूछा, 'नेताजी, अब क्या करेंगे?' नेताजी बोले, 'हम नई पार्टी बनाएंगे, पुरानी पार्टी पर आरोप लगाएंगे, फिर नई पार्टी को पुरानी बनाएंगे, और पुरानी को नई। बस, जनता को उलझाए रखेंगे!'

अब नेताजी राजनीति से सन्यास लेने की सोच रहे थे, लेकिन उनकी नाक ने इसकी इजाजत नहीं दी। आखिरी बार जब उन्हें किसी ने संसद भवन के गेट पर देखा, तो वे सोच रहे थे, काश, जनता की याददाश्त मेरी नाक जितनी लंबी होती!

मुद्दा

डॉ. राघवेन्द्र शर्मा

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

# भारत की चुनाव प्रणाली ने वैश्विक स्तर पर पाई प्रामाणिकता

**वर्ष 1982 में केरल राज्य के उत्तरी पारावुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में पहली बार ईवीएम आधारित चुनाव प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। यह चुनाव उम्मीद से कहीं आगे जाकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मतदान के परिणाम भी पारंपरिक मत पत्रों पर आधारित चुनाव प्रणाली की अपेक्षा बहुत जल्दी प्राप्त हो गए। अपवाद स्वरूप प्राप्त बेहद सीमित आपत्तियों के अलावा कोई उल्लेखनीय खामी सामने नहीं आई, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आधारित चुनाव प्रणाली को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। बाद में जब विधानसभाओं और लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ तो इसकी पारदर्शिता और सात्विकता पर अनेक उंगलियां उठीं। फलस्वरुप देश के चुनाव आयोग ने राज्यसभा, लोकसभा, विभिन्न प्रांतो की विधानसभाओं के अलावा कलेक्टरेटों में, और जहां तक संभव हो सकता था वहां तक इन मशीनों का प्रदर्शन किया।**

वैश्विक स्तर पर स्थापित सत्य है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। एक ऐसा देश जहां लगभग डेढ़ अरब लोग निवास करते हैं। जनसंख्या के लिहाज से यह इतना बड़ा आंकड़ा है कि भारत का एक-एक शहर अपने भीतर एक से अधिक राष्ट्र समाहित कर लेने की हद तक फैला हुआ है। फिर भी हमारे देश के नागरिक बेहद आधुनिक चुनाव पद्धति के माध्यम से ग्रामीण, शहरी, जनपदीय, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भली-भांति हर प्रकार की सरकारों का गठन लोकतांत्रिक प्रणाली से कर रहे हैं। आज जब स्वयं को विकासशील और विकसित कहने वाले अनेक राष्ट्र मत पत्र आधारित चुनाव प्रणाली में ही उलझे हुए हैं, लेकिन तब हमारा भारत देश अत्यधिक चुनाव प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तक का सफर तय कर चुका है। एक जमाना ऐसा था जब हमारे यहां भी मत पत्र प्रणाली पर आधारित चुनाव प्रक्रिया व्यवहार में लाई जाती थी। लेकिन इस देश ने और देश के चुनाव आयोग ने मतपत्र प्रणाली पर आधारित चुनाव प्रक्रिया अपनाते हुए अनेक प्रतिकूल, बेहद खतरनाक परिणाम भी देखे। कई दशकों तक येन केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज बने रहने अथवा सत्ता पर काबिज होने के लिए मतदान प्रणाली की सात्विकता का हरण किया जाता रहा। जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर अनेक अवसरवादी, सत्ता लोलुप और नैतिकता से लगभग नाता तोड़ चुके घाघ राजनेता बूथ कैपचरिंग करते रहे। नकली मत पेटियों से असली मत पेटियां बदली जाती रहीं। चुनावी टीम को एक प्रकार से अपहृत करते हुए मनपसंद उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर यंत्रवत ठप्पे लगाए जाते रहे। इस पाप पूर्ण कृत्य का विरोध करने पर जागरूक मतदाताओं, चुनाव कराने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों, पत्रकारों को मौत के घाट उतारा जाता रहा। फलस्वरुप एक समय ऐसा भी आया जब गांव की पंचायत से लेकर देश की लोकसभा तक, विभिन्न सदनों में, बाहुबल के बल पर जीत कर आए, आपराधिक पृष्ठभूमि के जनप्रतिनिधियों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ गई। जब देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न चुनाव रक्त रंजित होने लगे, तब देश के प्रबुद्ध वर्ग को चिंता हुई। यह विमर्श किए जाने लगे कि ऐसा क्या किया जाए, जिससे चुनाव में रक्तपात ना हो। निर्वाचित होकर भी वही लोग सदन में पहुंचे मतदाता जिन्हें स्वेच्छा से चुनना चाहते हों। तब देश के सामने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विकल्प सामने आया। तमाम अध्ययनों के बाद, कोई खामी शेष न रह जाए यह सुनिश्चित करने के बाद, अपराधी किस्म के नेता भूत कैपचरिंग ना कर पाएं यह संतुष्टि करने के बाद, अंततः देश ने ईवीएम यानि कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आधारित चुनाव प्रणाली को अपना लिया। इस प्रकार वर्ष 1982 में केरल राज्य के उत्तरी पारावुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में पहली बार ईवीएम आधारित चुनाव प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। यह चुनाव उम्मीद से कहीं आगे जाकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मतदान के परिणाम भी पारंपरिक मत पत्रों पर आधारित चुनाव प्रणाली की अपेक्षा बहुत जल्दी प्राप्त हो गए। अपवाद स्वरूप प्राप्त बेहद सीमित आपत्तियों के अलावा कोई उल्लेखनीय खामी सामने नहीं आई, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आधारित चुनाव प्रणाली को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। बाद में जब विधानसभाओं और लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ तो इसकी पारदर्शिता और सात्विकता पर अनेक उंगलियां उठीं। फल स्वरुप देश के चुनाव आयोग ने राज्यसभा, लोकसभा, विभिन्न प्रांतो की विधानसभाओं के अलावा कलेक्टरेटों में, और जहां तक संभव हो सकता था वहां तक इन मशीनों का प्रदर्शन किया। सभी स्तर के आम और खास लोगों को इसकी प्रक्रिया बताई व दिखाई गई। साथ में शिकायतें सुझाव एवं आपत्तियां मंगाई गईं। हर एक शिकायत, आपत्ति और सुझाव पर बारीकी से विचार विमर्श हुआ। जो सुझाव उचित लगे उन्हें व्यवहार में लाया गया। जिन शिकायतों अथवा आपत्तियों में तार्किकता दिखाई दी, उन्हें पूरी ईमानदारी से निराकृत किया गया। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सात्विकता, उनकी पारदर्शिता को लेकर व्यापक स्तर पर संतुष्टि काबिज हो गई, तब कहीं जाकर इस चुनाव प्रणाली को वृहद स्तर पर व्यवहार में लाया गया। यह बात और है कि चुनाव में मुंह की खाने वाले राजनेता और राजनीतिक दल, जीतने वाले सत्ताधारी दल पर और चुनाव आयोग पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में धांधलियां करने के आरोप मढ़ते रहे। लेकिन वह लोग कभी भी कोई तार्किक तथ्य सामने ना रख सके, जिससे उनके आरोपों को सही न माना गया। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आधारित चुनाव प्रणाली भली भांति चुनावी दायित्वों का निर्वहन कर रही है। सब कुछ ठीक-ठाक होने के बावजूद केवल चुनाव आयोग ही नहीं, अपितु देश इस बात को लेकर चिंतित है कि हमारे यहां मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत अभी कम ही बना हुआ है। इस समस्या को लेकर जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक देश के नागरिक बार-बार के चुनावों से तंग आ चुके हैं। बात सही भी है, कोई साल और महीना ऐसा नहीं बीतता जब देश के किसी प्रांत, जिले, नगर, जनपद अथवा गांव में चुनाव संपन्न ना होता हो। परिणाम स्वरूप आम आदमी तो बार-बार के चुनावों से तंग तो आया ही, चुनावी आचार संहिता के बने रहने से विकास कार्य भी प्रभावित बने रहते हैं । आम आदमी के साथ-साथ विकास की गति को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक राष्ट्र एक चुनाव की पुरजोर वकालत कर रहे हैं। यदि यह चुनाव प्रणाली देश में लागू होती है तो फिर आम आदमी को विभिन्न पदों के निर्वाचन हेतु बार-बार मतदान केंटो पर नहीं भटकना पड़ेगा। इससे मतदाताओं के अंतर्मन में गहरे तक पैठ चुकी ऊब से छुटकारा मिलेगा तथा मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सकेगा। इसी के साथ विकास कार्य भी निरंतरता के साथ संपादित किये जा सकेंगे।

इसका मतलब यह हुआ कि भारत की वर्तमान चुनाव प्रणाली बखूबी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। उसकी पारदर्शिता और सात्विकता वैश्विक स्तर पर प्रामाणिकता प्राप्त कर चुकी है। ऐसे में यदि एक और नई चुनाव प्रणाली की बात की जाए तो फिर सवाल यह खड़ा होता है कि जब सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है तो फिर एक और नया प्रयोग क्यों? इसका जवाब कुछ यूं हो सकता है कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, यह सोचकर हाथ पर हाथ रखकर बैठते हुए भविष्य की चुनौतियों का सामना नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए - अभी भी चुनाव कराने के लिए लाखों पोलिंग बूथ, करोड़ों चुनाव अधिकारी - कर्मचारी, सुरक्षा बलों की व्यापक स्तर पर तैनाती, भारी पैमाने पर आर्थिक खर्चे तथा आम आदमी की मतदान केंद्रों तक आवाजाही, वह समस्याएं हैं जिनका हल हमें आज ही ढूंढना होगा। क्योंकि जैसे-जैसे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, व्यवस्थाएं, नियुक्तियां और खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ते चले जाने हैं। इन सभी के निराकरण स्वरूप दिमाग में एक संभावित चुनाव प्रणाली का ध्यान आता है, जिसका नाम है ब्लॉकचेन आधारित वोटिंग सिस्टम। यदि इस प्रणाली पर व्यापक वार्ता, बहस, विमर्श आदि हों तो परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले सारगर्भित नतीजों से भारतीय लोकतंत्र के लिए नई संभावनाओं को तराशा जा सकता है। लेकिन इसके लिए, पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ब्लॉकचेन आधारित वोटिंग सिस्टम काम कैसे करेगा।

इसका सबसे पहले चरण होगा मतदाता का पंजीयन। यह आधार कार्ड या किसी डिजिटल आईडी का उपयोग करके चुनाव आयोग द्वारा ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है।

दूसरे कम पर आती है मतदान प्रक्रिया। इसे संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग प्रत्येक मतदाता को एक डिजिटल टोकन अथवा कोड प्रेषित करेगा, जिसके माध्यम से मतदाता जहां है वहीं से मान्यता प्राप्त गैजेट को माध्यम बनाकर अपने मनपसंद उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर सकेगा। बदले में उसे डिजिटल स्वरूप में ही तत्काल मतदान की रसीद चुनाव आयोग द्वारा भेजी जा सकेगी। मतदाता द्वारा चुनाव आयोग को भेजा गया उपरोक्त मतदान ब्लॉक चैन सिस्टम में दर्ज होगा जिसे बदला नहीं जा सकेगा।

तीसरे क्रम पर मतगणना की बारी आती है। होगा यह कि जैसे ही मतदान संपन्न होगा और मतगणना के लिए सिस्टम का सर्वर ऑन किया जाएगा, वैसे ही डिजिटल स्वरूप में मतगणना के परिणाम मतदान में इस्तेमाल किए गए गैजेट पर दिखाई देने लगेंगे। मतगणना में कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है, यह रुझान भी ठीक उसी प्रकार प्रदर्शित हो सकेंगे जिस प्रकार स्टॉक मार्केट में शेयरों के भाव उतार-चढ़ाव के रूप में देखा जाना प्रचलन में बना हुआ है। अंत में यह परिणाम भी देखा जा सकेगा कि चुनाव में कौन हारा और जीत किसके हिस्से में आई। ब्लॉक चैन वोटिंग सिस्टम के एक्सप्लोरर का उपयोग करके हार जीत का अंतर क्या रहा, यह भी बगैर लंबी प्रतीक्षा के तत्काल देखा जा सकेगा। खास बात यह कि इस चुनाव प्रणाली में भी डिजिटल रूप से दर्ज हुए आंकड़ों में किसी भी प्रकार का हेर फेर नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि सारा डेटा इंक्रिप्टेड और सुरक्षित ही रहने वाला है।

---

नक्सलवाद

रमेश सर्राफ धमोरा

लेखक पत्रकार हैं।

# समाप्त होने के कगार पर पहुंचा नक्सलवाद

पिछले छः दशकों से देश में नासूर बनकर उभरा नक्सलवाद अब समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। देश के गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में घोषणा की है कि 31 मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। गृह मंत्री द्वारा की गई यह एक बहुत बड़ी घोषणा है। गत 60 वर्षों से देश नक्सलवाद की समस्या से बुरी तरह पीड़ित रहा है। इस दौरान देश में कई सरकारें आई और चली गई मगर नक्सलवाद का नासूर दिनों-दिन बढ़ता ही रहा था। देश के कई प्रदेशों में तो बहुत बड़े हिस्से में नक्सलवादी अपनी समानांतर सरकार तक चलाते थे। नक्सलवाद प्रभावित जिलों में उनकी हुकूमत चलती थी। वहां केंद्र व राज्य सरकार का कोई असर नहीं दिखता था। नक्सलियों का फरमान ही अंतिम आदेश होता था जिसे लोग मानने को मजबूर थे। मगर अब परिस्थितियों पूरी तरह बदल चुकी है। केंद्र सरकार की नक्सलवाद से मुक्ति के अभियान की सफलता से नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। कई बड़े-बड़े नक्सली कमांडर सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं या फिर उन्होंने सरेंडर कर अपनी जान बचा ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनो कहा कि नक्सलवाद मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटाकर 6 कर दिया है। शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मोदी सरकार के दृष्टिकोण पर रोशनी डालते हुए और सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा था कि मोदी सरकार सर्वव्यापी विकास के लिए अथक प्रयासों और नक्सलवाद के खिलाफ दृढ़ रुख के साथ सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की कुल संख्या पहले 38 थी। इनमें से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या अब घटकर 6 हो गई है। साथ ही चिंता के जिलों और अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में भी कमी आई है। नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित छह जिलों में अब छत्तीसगढ़ में चार जिले बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला व महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला शामिल है। इसके अतिरिक्त चिंता के जिलों की संख्या जिन्हें गहन संसाधनों और ध्यान की आवश्यकता है 9 से घटकर 6 रह गई है। ये जिले आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू, मध्य प्रदेश में बालाघाट, ओडिशा में कालाहांडी, कंधमाल और मलकानगिरी और तेलंगाना में भद्राद्री-कोठागुडेम हैं।

अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या जो नक्सली गतिविधि का भी सामना कर रहे हैं लेकिन कम हद तक 17 से घटकर 6 हो गई है। इनमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, गरियाबंद और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चैकी, झारखंड का लातेहार, ओडिशा का नुआपाड़ा और तेलंगाना का मुलुगु जिला शामिल हैं। इन जिलों को उनके पुनर्निर्माण और विकास में सहायता करने के लिए केंद्र सरकार विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों को 30 करोड़ रुपये मिलते हैं। जबकि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में अंतराल को भरने के लिए चिंता वाले जिलों को 10 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं। इन क्षेत्रों की जरूरतों के अनुरूप विशेष परियोजनाओं को भी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते वर्ष 2025 में अब तक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ों में कम से कम 130 नक्सली मारे गए हैं। इनमें से 110 से ज्यादा बस्तर संभाग में मारे गए जिसमें बीजापुर और कांकेर समेत सात जिले शामिल हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से 105 से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 2025 में अब तक 164 ने आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं इससे पहले वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। अभी तक कुल 15 शीर्ष नक्सली नेताओं को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है।

वर्ष 2014 तक कुल 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन थे जबकि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में इनकी संख्या बढ़कर 612 हो गई है। इसी प्रकार, 2014 में देश में 126 जिले नक्सलप्रभावित थे लेकिन 2024 में सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या घटकर मात्र 12 रह गई है। पिछले 5 वर्षों में कुल 302 नए सुरक्षा कैंप और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स बनाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2004 से 2014 तक देश में नक्सलवाद से जुड़ी 16,463 हिंसक घटनाएं हुई थीं। लेकिन पिछले 10 वर्षों में इसमें 53 प्रतिशत कमी आई है। वर्ष 2004 से 2014 तक विभिन्न नक्सली हमलों और नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान 1851 सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी। लेकिन पिछले 10 साल में सुरक्षाबलों के हताहत होने की संख्या 73 प्रतिशत घटकर 509 रह गई है। वहीं 2004 से 14 के बीच नक्सली हमलों में 4,766 नागरिकों की मौत हुई थी। 2014 से 2024 के बीच यह आंकड़ा 70 प्रतिशत घटकर 1495 रह गया है।

गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे जा चुके हैं, 104 को गिरफ्तार किया गया है और 164 ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था, 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। पिछले 20 वर्षों में 2,344 सुरक्षाकर्मियों ने नक्सलियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई है पिछले दो दशकों में अकेले नक्सली हमलों में 6,258 लोग मारे गए हैं। जब देश में नक्सलवाद अपने चरम पर था तब 8 करोड़ लोगों को प्रभावित किया था। जिनमें मुख्य रूप से आदिवासी थे। यह आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में फैले एक लाल गलियारे के साथ 10 राज्यों में फैला हुआ था।

सरकार एक तरफ जहां नक्सलवाद को समाप्त करने की घोषणा कर रही है वहीं दूसरी तरफ शहरी नक्सलवाद जिसे अर्बन नक्सलवाद भी कहा जाता है तेजी से उभर रहा है। यह पारंपरिक ग्रामीण नक्सलवाद से अलग है क्योंकि इसका फोकस शहरों और शहरी इलाकों में होता है। शहरी नक्सली विचारधारा के समर्थक, जिनमें शिक्षाविद, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल होते हैं नक्सलवादी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करते हैं। वे विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक माध्यमों से अपनी विचारधारा फैलाते हैं और व्यवस्था के खिलाफ असंतोष को भड़काते हैं।

देश में नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार के समग्र प्रयासों का असर दिखने लगा है। सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अब देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में कमी हो रही है। सरकार ने नक्सलवाद-मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। देश में वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या में कमी आना इस आंदोलन की समाप्ति के संकेत है।

नक्सलवादी आंदोलनकारियों ने अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हजारों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों ने भी नक्सलवादी विरोधी अभियान में अपनी शहादत दी है। एक समय था जब देश के 10 प्रांतो में नक्सलवादियों की तूती बोलती थी। इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर भी हमला कर दिया था। जगदलपुर में तो नक्सलवादियों ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की हत्या कर सनसनी फैला दी थी।

मगर अब केंद्र सरकार की नीतियों के कारण एक तरफ जहां इन पर दबाव बढ़ा है वहीं उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में सरकार ने विकास की योजनाएं प्रारंभ कर उनका जन समर्थन समाप्त कर दिया है। कई बड़े नक्सली कमांडरों का एनकाउंटर होने के बाद डर कर बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। जिससे आने वाले समय में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति व्याप्त होगी। जो सरकार व आमजन की एक बड़ी जीत होगी।

---

सामयिक

अवधेश कुमार

लेखक पत्रकार हैं।

# मुर्शिदाबाद हमारी चिंता का कारण होना चाहिए

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से लेकर मध्यप्रदेश का गुना और इसके पहले नागपुर, मलाड आदि की घटनाओं से निस्संदेह देश को डरना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं कि डर कर चुपचाप बैठ जायें बल्कि इन घटनाओं में लगातार दिख रहे यथार्थ को पहचान कर उसके अनुरूप व्यवहार तय करने का समय है। मुर्शिदाबाद से भागीरथी नदी में नाव पर बैठकर पलायन करते और फिर मालदा जिले में उतरते लोगों की तस्वीरें किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को अंदर से हिला देगी। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में गैर मुस्लिमों, हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा पर अपनी भौंहें टेढ़ी करते हैं, अपने देश के बारे में क्या कहेंगे? मालदा के पारलालपुर हाई स्कूल में शरण लिए लगभग 500 लोगों की तस्वीरें एवं वक्तव्य देश के सामने है। इनमें तीन दिन के नवजात से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं। स्थानीय स्थानीय लोगों ने कम से कम उन्हें गले लगाया और खाने-पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार की यात्रा के बाद पार्टी और दूसरे हिंदू संगठन भी सक्रिय हुए। लेकिन क्या किसी को याद है 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हिंदू असम और झारखंड में पहुंच गए थे। वे आज तक लौटे या नहीं लौटे देश को पता भी नहीं था। जब असम के मुख्यमंत्री हिमांतो विस्वासर्मा ने अपनी पोस्ट लिखी तब इसकी जानकारी हुई। वर्तमान घटना में पलायन कर गए लोग मुर्शिदाबाद के धुलियान के हैं। वे बता रहे हैं कि घरों में आग लगा दी, मारपीट की गई, अब न घर रहा न खाने को राशन बचा हम करें तो क्या करें, जो कुछ था वह सब लूट कर ले गए। मणिपुर पर तूफान खड़ा करने वाले और यात्रा करने वाले राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के नेताओं की चुप्पी ज्यादा डरावनी है। मणिपुर देश के लिए सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए किंतु क्या मुर्शिदाबाद नहीं?

यही वह प्रश्न है अलग-अलग ऐसी घटनाओं और संदर्भों में जिनका उत्तर भारत स्पष्ट रूप से कभी नहीं दे सका। धुलियान में एक गरीब पिता पुत्र की हत्या कर दी गई जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। मूर्तिकार से किसका वैर का हो सकता है? लोग कह रहे हैं कि उनकी पानी की टंकी में जहर मिला दिया गया। इसमें कितनी सच्चाई है अभी तक तो ममता बनर्जी सरकार को टंकियां जांच करके बता देना चाहिए था। नहीं बताने का मतलब? कई तालाबों में मछलियों सहित अन्य जीव मरे पाए गए। यानी हमलावर घोषणा कर रहे थे कि सारे पानी में जहर मिला देंगे तो संभवत उन्होंने तालाब में ऐसा किया। टीवी कैमरों के माध्यम से देश ने वहां की हिंसा देखी। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक भी अलग-अलग क्षेत्र में हिंसा हो रही थी। शमशेरगंज सहित कई स्थानों में बीएसएफ की टीम पर गोलीबारी की गई। बीएसएफ कई घरों में जमा किए पत्थर हटा रही है। कलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के कारण केंद्रीय सुरक्षा बलों की 17 कंपनियां तैनात की गई अन्यथा पश्चिम बंगाल पुलिस के रहते क्या हो रहा था और क्या होता इसकी कल्पना से रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भले आप आलोचना करिए और उनके विरोधी हों। इन विकट परिस्थितियों में हिंदू समाज के साथ इनके अलावा कोई खड़ा नहीं दिखता। अन्य पार्टियों की स्थानीय ईकाइयां सच देखती हैं, भूमिका निभाता भी चाहती हैं लेकिन प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में नहीं करती। सबसे बुरी स्थिति कांग्रेस के पिछले लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की है। उनकी बात पार्टी में ही सुनने वाला कोई नहीं क्योंकि यहां पूरे देश का मुस्लिम वोट बैंक प्रभावित होता है। स्थानीय भाजपा के कई नेताओं ने प्रदेश में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम या अफस्पा लागू करने की मांग की है। आपको यह भले नागवार गुजरे किंतु पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखिए और निष्कर्ष निकालिए कि वहां क्या किया जाना चाहिए? किसी का वक्फ संशोधन कानून से विरोध है तो उसका तरीका हिन्दुओं पर हमला कैसे सकता है? वैसे तो वक्फ कानून में ऐसा कुछ नहीं है जिसे मुसलमान या इस्लाम के विरुद्ध साबित किया जा रहा है। इस तरह की जहर फैलाने वाले वास्तव में स्वयं मुस्लिम समाज के ही दुश्मन हैं। बावजूद अगर आपको विरोध करना है तो इसके लिए हिंदुओं के घरों पर हमले करने, धर्म स्थलों को क्षतिग्रस्त करने, हत्याएं करने, दुकान घर जलाने आदि की क्या आवश्यकता है?

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशव्यापी विरोध का आह्वान किया था। क्या हिंसा के लिए उसे दोषी नहीं माना जाना चाहिए? हमलावरों की तैयारी कितनी थी यह है इसका अनुमान इसी से लगाइए कि पलायन कर गए लोग बता रहे हैं कि वे गैस सिलेंडरों को खोलकर दियासलाई से आग लग रहे थे और पेट्रोल डाल रहे थे। आगजनी, पत्थरबाजी और गोली चलाने के लिए पहले की तैयारी चाहिए। गुना में हनुमान जयंती की शोभायात्रा पर जितनी भारी संख्या में पत्थर चले और आगजनी हुई उसकी तैयारी एकाएक संभव नहीं। इसी तरह हजारीबाग में हुआ। पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि हिंदुओं से जुड़े उत्सवों, शोभा यात्राओं, प्रतिमा विसर्जनों आदि पर इसी तरह पत्थरों से हमले होते हैं फिर अग्निकांड होता है। इससे भी डरावना सच यह है कि कोई बड़ा मुस्लिम नेता या संगठन हिंसा के विरुद्ध मुखर होकर सामने नहीं आते। दूसरे पक्ष को ही दोषी ठहरने का अभियान चलता है और कहा जाता है कि हमले उनके उकसाने पर हुए। किसी के उकसाने पर हजारों- लाखों की संख्या में पत्थर, पेट्रोल बम पैदा हो सकते। मुर्शिदाबाद पर बंगाल की ममता सरकार में मंत्री सिद्धीकुल्ला चौधरी कह रहे हैं कि हिंसा में बाहरी और भाजपा के लोग शामिल थे, वे बीएसएफ की गोली से मारे गए। जंगीपुर के स्थानीय तृणमूल सांसद खलीलुर रहमान का बयान भी यही है। तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष का वक्तव्य है कि एक राजनीतिक दल ने बाहर से अपराधियों को लाकर बीएसएफ के सहयोग से मुर्शिदाबाद में तांडव मचाया है।

ममता सरकार और उनकी पार्टी का स्टैंड यही है तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। यह पहली बार नहीं है। पिछले वर्ष लगभग इसी समय जब वर्धमान जिले में एक बम विस्फोट की जांच करने गई एनआईए की टीम पर जबरदस्त हमले हुए। विस्फोट बम बनाने के दौरान हुई और मरने वाले तीनों तृणमूल के थे। जाहिर है इसमें किसके गले तक हाथ पहुंचता। चाहे शाहजहां शेख पर कार्रवाई करने गई टीम हो या अन्य जगह वहां हमेशा बड़ी संख्या में उन्हें हिंसक विरोध का सामना करना पड़ता है खदेड़ा जाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर पूरी सरकार, पार्टी हमला बोल शैली में साथ खड़ी होती है। जब सरकार और पुलिस प्रशासन का भय नहीं हो तो कट्टरवादी तत्व ऐसे ही उन्माद फैलाता है।

तो सच को सच की तरह देखिए फिर रास्ता निकालिए कि क्या हो सकता है। बंगाल संपूर्ण देश के लिए ऐसा डरावना प्रश्न बना हुआ है जिसका अभी तक उत्तर नहीं मिला है। धीरे-धीरे दूसरे राज्यों में भी हिंदू उत्सवों प्रतिमा विसर्जनों शोभा यात्राओं आदि पर हमले की प्रवृत्तियां बढ़ीं हैं। उनके संदर्भ में हिंदू संगठनों, सरकारों तथा पार्टियों को नए सिरे से अपनी स्थाई रणनीति और व्यवहार तय करनी होगी। मुस्लिम समुदाय के अंदर भी उदारवादी तबके को उनके विरुद्ध खुलकर सामने आना चाहिए। यह देश बचाने का प्रश्न है। लेकिन जो समाज अपनी आत्मरक्षा और प्रतिरोध की शक्ति खो देता है उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। इस समय हिंदू समाज संविधान के तहत हिंसा या गलत के प्रतिरोध के अंधकार तक का इस्तेमाल करने का साहस नहीं दिख रहा। कम से कम ऐसी घटनाओं के विरोध में अहिंसक तरीके से धरना प्रदर्शन जैसे प्रतिरोध तो होना चाहिए था। बावजूद बंगाल जैसी स्थिति किसी की नहीं। केरल की कुख्याति भी बंगाल के सामने कमजोर काफ छोटी हो गई है। न्यायालय की स्थिति यह है कि 2021 में हिंदुओं के पलायन का मामला उच्चतम न्यायालय में आया और सुनवाई के दौरान एक बंगाली न्यायमूर्ति ने पहले अपने को अलग किया। फिर सुनवाई आरंभ हुई और एक और बंगाली जज साहब ने स्वयं को अलग कर लिया। इस कारण वह बाधित रही। वैसे भी न्यायालयें ऐसी बढ़ती या स्थाई हो चुकी प्रवृत्तियों का समाधान नहीं कर सकतीं।

# चुनावी चेकिंग में पकड़ी गई इंद्री व्हिस्की के प्रकरण में आरोपी दोषमुक्त

**40 लाख रुपए की जब्त शराब पर न्यायालय ने सुनाया फैसला**

**बैतूल।** विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान चेकिंग के तहत पकड़े गए इंद्री सिंगल माल्ट व्हिस्की के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। पिक्काडेली कंपनी की यह इंद्री सिंगल माल्ट व्हिस्की खंडवा-बैतूल मार्ग पर थाना मोहदा क्षेत्र में ग्राम देसली स्थित चेकिंग नाके से पकड़ी गई थी, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए आंकी गई थी। पुलिस ने मालवाहक वाहन से भारी मात्रा में शराब जब्त करते हुए आरोपी चालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और सुनवाई के बाद आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया।

मामले में अधिवक्ता कलश दीक्षित ने पैरवी की और न्यायालय ने 16 अप्रैल 2025 को फैसला सुनाते हुए आरोपी को संदेह का लाभ देते बरी कर दिया। मामला थाना मोहदा क्षेत्र का है, जहां 21 अक्टूबर 2023 को सुबह 9ः30 बजे देसली चेकपोस्ट (खंडवा-बैतूल रोड) पर चुनावी जांच के दौरान टाटा कंपनी की योद्धा 1700 सफेद रंग की पिकअप क्रमांक यूपी-15-एफटी-1984 को रोका गया था। पुलिस ने वाहन में 405 लीटर (750 एमएल की 90 पेटी) और 45 लीटर (60 एमएल की 5 पेटी) कुल 450 लीटर व्हिस्की पाई थी, जिसे वैध अनुज्ञप्ति के बिना परिवहन का मामला बनाकर जब्त कर लिया गया था। वाहन चालक सोनू पिता बालकिशन को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

प्रकरण में बचाव पक्ष के अधिवक्ता कलश दीक्षित ने अदालत के समक्ष यह दलील रखी कि वाहन चालक के पास शराब परिवहन से संबंधित सभी वैध दस्तावेज मौजूद थे। पुलिस की ओर से भी साक्ष्यों में यह बात स्वीकार की गई कि दस्तावेज हरियाणा और नागपुर के आबकारी विभाग द्वारा जारी किए गए थे और दिनांक 21 अक्टूबर 2023 तक वैध थे।

पुलिस ने यह आरोप लगाया था कि वाहन गलत मार्ग से शराब का परिवहन कर रहा था, लेकिन बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मार्ग में परिवर्तन कोई अपराध नहीं है जब तक कि अनुज्ञप्ति वैध हो। साथ ही, कार्यवाही के दौरान न तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हुई और न ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति दर्ज की गई, जो चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है। इस संबंध में अधिवक्ता कलश दीक्षित ने बताया कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत गवाहों के कथनों में विरोधाभास पाए गए। पंचनामा तैयार करने वाले गवाहों को किसी विधिवत नोटिस के तहत नहीं बुलाया गया था और उनमें से एक घटनास्थल से 10 किमी दूर का निवासी था। साक्ष्य के अभाव, वैध दस्तावेजों की उपलब्धता और प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त किया।

## जिला न्यायालय बैतूल में हृदय रोग एवं जांच शिविर का होगा निःशुल्क आयोजन

**बैतूल।** जिला न्यायालय बैतूल में नोबल मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल भोपाल के द्वारा निःशुल्क हृदय रोग एवं जांच शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर में हॉस्पिटल के विशेषज्ञ जांच करेंगे और परामर्श दिया जाएगा। हॉस्पिटल प्रबंधक एवं अधिवक्ता दिग्विजय सिंह एवं अधिवक्ता राघवेंद्र रघुवंशी द्वारा जानकारी दी गई है कि जिला न्यायालय कार्यालय बैतूल में 21 अप्रैल दिन सोमवार को न्यायालय परिसर में हृदय रोग एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जायेगा। जिला अभिभाषक संघ के सहयोग से शिविर में न्यायाधीशों, अधिवक्तागणों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं परिजन का स्वास्थ्य परीक्षण कर निशुल्क हृदय की इको जांच, व अन्य हृदय से संबंधित जांचे की जायेगी। परीक्षण में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एवं आदि जांचे भी की जायेगी। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष संजय मिश्रा ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य स्वास्थ्य परीक्षण के साथ-साथ स्वास्थ्य जागरूकता एवं स्वस्थ व्यवहारों को बढ़ावा देना भी है।

## ओजस शिक्षण संस्थान के संचालक अनिल वर्मा वेटरन अचीवर अवॉर्ड से सम्मानित

**बैतूल।** ओजस शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान मोरन ढाना आमला के संचालक अनिल वर्मा को सेना के चक्रा कोर मुख्यालय में आयोजित समारोह में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी द्वारा वेटरन अचीवर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन सेवानिवृत्त सैनिकों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने सेवा काल और सेवानिवृत्ति के बाद समाज में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। ओजस शिक्षण संस्थान पूर्व सैनिकों द्वारा संचालित एक उत्कृष्ट संस्था है, जो ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों को न केवल गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण, खेल-कूद एवं अनुशासन की दिशा में भी मार्गदर्शन दे रही है। यहां से शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र न सिर्फ शैक्षणिक रूप से सफल हो रहे हैं, बल्कि एक संस्कारी, जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में उभर रहे हैं।सम्मान प्राप्ति के अवसर पर अनिल वर्मा ने कहा कि यह सफर आसान नहीं था।

# बुजुर्ग शांति बाई को कलेक्टर ने दिलाया न्याय, वर्षों पुरानी जमीन सम्बंधी समस्या का तत्काल किया समाधान

**बैतूल।** शुक्रवार को घोड़ाडोंगरी पहुंचे कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने राजस्व विभाग की समीक्षा के साथ यहां जनसामान्य की समस्याएं भी सुनी। बड़ी आस लिए यहां पहुंची बुजुर्ग शांति बाई ने नम आंखों से अपनी पीड़ा कलेक्टर को बताई। महिला ने बताया कि उनके परिजन द्वारा उनकी कृषि भूमि पर छल से जबरन कब्जा कर उन्हें कृषि कार्य नहीं करने नहीं दिया जा रहा है और चतुर सीमा गलत बताकर विक्रय कर दिया है। उनके मकान पर भी नहीं रहने दिया जा रहा है। उनकी भूमि पर उनके पोता सत्यम का नामांतरण आदेश के होने के बाद भी आज तक उनके नाती का नाम दर्ज नहीं किया गया हैं। महिला की समस्या को गंभीरता से सुन कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने नामांतरण आदेश बुलवाया और आदेश अमल नहीं होने पर पटवारी को फटकार लगाई। उन्होंने मौके पर ही शांतिबाई के नाती का नाम दर्ज करवाया और खसरा की कापी प्रदान की गई। यहीं नहीं बुजुर्ग महिला और उनके नाती को कलेक्टर ने अपने वाहन में सम्मान पूर्वक बैठाकर उनके साथ उनकी ग्राम टैमरूरैयत स्थित कृषि भूमि पर पहुंचे। यहां उन्होंने जमीन के दस्तावेज का अवलोकन किया जिसमें पाया कि चतुर्सीमा गलत लगाकर परिजन द्वारा विक्रय कर दी गई है जिस पर कलेक्टर ने तहसीलदार को रजिस्ट्री दुरुस्त करवाने और सही चतुर सीमा अनुसार समान रूप से बंटवारा व नक्शा संशोधन किए जाने के निर्देश दिए। मौके पर कब्जा भी दिलवाया गया। इस दौरान महिला के खेत में कुआं क्षतिग्रस्त पाए जाने पर कलेक्टर ने मनरेगा योजना के तहत कुएं की तत्काल मरम्मत करने के निर्देश ग्राम पंचायत सचिव को दिए। यह कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।

### मकान की मरम्मत कराने के दिए निर्देश

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बुजुर्ग महिला के मकान का भी जायजा लिया। वर्षों से बंद मकान खुलवा कर मकान क्षतिग्रस्त पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मकान की मरम्मत करवाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही जन सहयोग से मकान की छत बदले जाने का भी वादा किया। मकान के पीछे किया पड़ोसी का अतिक्रमण हटवाया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ भी चर्चा कर कहा कि ग्राम में शांतिबाई को किसी भी तरह की परेशानी न हो। सभी उनका सहयोग करें। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तत्काल सूचना तहसील कार्यालय में दे।

### सत्यम को मिलेगा शासकीय योजनाओं का लाभ

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने शांति बाई के पोता सत्यम को भी महिला एवं बाल विकास विभाग की मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं से लाभान्वित कराए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। उल्लेखनीय है कि शांति बाई के पोता सत्यम के पिता का असामयिक निधन हो गया था, जिसके बाद से ही सत्यम अनाथ हो गया। सत्यम का पालन पोषण शांतिबाई ही कर रही थी।

### शांति बाई ने सरकार का माना आभार

जमीन और मकान संबंधी बरसों पुरानी समस्या से जूझ रही शांति बाई का त्वरित समाधान होने पर बहुत खुश नजर आई, उन्होंने बताया कि वे कभी सोच भी नहीं सकती थी। उनकी समस्या का इतने जल्दी और गरिमा के साथ समाधान हो सकेगा। मैं और मेरा नाती शासन के आभारी हैं। इस दौरान शांतिबाई ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी मन से याद किया।

# थाने में घुसकर दो पुलिसकर्मियों पर किया हमला

### ● एसआई और आरक्षक घायल

**बैतूल।** जिला मुख्यालय के थाना कोतवाली परिसर में शुक्रवार शाम एक युवक ने दो पुलिसकर्मियों पर शराब की बोतल से हमला कर दिया। घटना सायंकाल करीब 4.30 बजे की बताई जा रही है। इस घटना में एसआई पंचम सिंह उइके और आरक्षक हर्षित डांगे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद दोनों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसआई पंचम सिंह उइके थाने में फरियादी की रिपोर्ट दर्ज कर रहे थे, तभी दो युवक थाने पहुंचे। उनमें से एक युवक ने बताया कि मुझे जान से मारने की धमकी दी है मेरी रिपोर्ट लिखो। एसआई ने युवक को थोड़ा रूकने के लिये कहा और रिपोर्ट लिखने के लिए अपने साथी को निर्देशित किया। इसी दौरान युवक अचानक आग बगुला हो गया और अपनी कमर से फंसी शराब की बोतल निकालकर खुद को नुकसान पहुँचाने लगा। पुलिसकर्मियों ने जब उसे रोकने की कोशिश की, तो युवक ने पहले एसआई पंचम सिंह उइके के सिर पर बोतल दे मारी। जिसके बाद बीच बचाव करने आये आरक्षक हर्षित डांगे को भी युवक ने घायल कर दिया। जिससे दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने तत्काल हमलावर युवक और उसके साथी को हिरासत में ले लिया। घायल दोनों पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। बताया जा रहा है कि हमलावर युवक कुछ समय पहले ही हत्या के मामले में जेल से छूटकर बाहर आया है। पुलिस ने हमलावर शराबी युवक से पूछताछ शुरू कर दी है और घायल पुलिसकर्मियों का मेडिकल करवाया जा रहा है। जिसके बाद युवकों पर मामला दर्ज किया जायेगा।

# बाबा साहेब अंबेडकर की जन्म जयंती पखवाड़े पर व्याख्यान माला का आयोजन

**बैतूल/भौंरा।** मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद ब्लॉक शाहपुर के अंतर्गत एकलव्य आदर्श विद्यालय शाहपुर में बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन में मुख्य वक्त के रूप में रिटायर्ड शिक्षक कापसे गुरुजी, चंदूलाल महोबिया, जेडी झरवड़े, संभाग समन्वयक नर्मदापुरम कोशलेश तिवारी, ब्लाक समन्वयक संतोष राजपूत एवं सभी परामर्शदाता, नवअंकुर संस्थाओं के सदस्य, छात्र-छात्राएं, ग्राम के नागरिक द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर श्री कापसे द्वारा बताया गया कि बाबा साहेब अंबेडकर भारत देश के ऐसे नागरिक थे, जिनके पास 32 डिग्री प्राप्त की थी। साथ ही पूरे विश्व में बुद्धिमानी में छठवें नंबर पर थे, उन्हें विश्व में सिंबल आफ नालेज के रूप में जाना जाता है। उनके प्रयासों से अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़े, शोषित, दलित वर्गों को समानता का एक उचित और स्थान मिला। श्री तिवारी द्वारा बताया गया कि बाबा साहब ने समाज में छुआछूत को दूर करने का सफल प्रयास किया, जो आज हम यहां एक समान रूप से बैठे हैं। वह साक्षात रूप से दिख रहा है। ब्लॉक समन्वयक संतोष राजपूत ने सभी उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

# लोनिया रेत खदान का हुआ सीमांकन, ग्रामीणों ने लिखित में कहा बहकावे में आकर की झूठी शिकायत

**बैतूल/भौंरा।** मंगलवार को सारनी के पास मौजूद ग्राम पंचायत लोनिया की तवा नदी पर स्वीकृत रेत खदान के सीमांकन का कार्य किया गया। सीमांकन के लिए अवैध रेत उत्खनन की शिकायत करने वाले वाइल्डलाइफ और एनवायरनमेंटलिस्ट पत्रकार कल्याण परिषद घोड़ाडोंगरी के ब्लॉक अध्यक्ष आदिल खान को हमराह रख खनिज विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग ने यह संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इस कार्यवाही में स्वीकृत रेत खदान अवैध उत्खनन वाले क्षेत्र से लगभग आठ सौ मीटर दूर पाई गई। जानकारी के मुताबिक़ जनवरी में कुछ रेत माफियाओं द्वारा ग्रामीणों को ग़लत जानकारी देकर आदिल के खिलाफ रेत के अवैध उत्खनन की झूठी शिकायत करवाई थी। जिसके बाद आदिल ने पुलिस-प्रशासन को पहले हुई जांचों के दस्तावेज़ उपलब्ध कराए एवं बताया कि स्वीकृत खदान को छोड़कर अन्य स्थानों से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। आप को बता दें कि आदिल खान एक वाइल्डलाइफ और एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो लंबे समय से लगातार पर्यावरण और सामाजिक जागरूकता को लेकर कार्य कर रहें हैं। पूर्व में भी अवैध उत्खनन को प्रशासन ने उनकी शिकायत पर ही बंद करवाया था। जाँच के बाद खदान का संयुक्त रूप से सीमांकन किया गया, तो स्थिति स्पष्ट हो गई।

**आदिल खान की लड़ाई को मिली सफलता**

### इनका कहना–

ट्ठहमें सीमांकन के आदेश दिए गए थे, हमने आदिल खान को हमराह लेकर लोनिया रेत का सीमांकन किया और सीमांकन कराने का पंचनामा पेश कर दिया है।

**- छाया बंसोड़े, पटवारी लोनिया**

सतपुड़ा मेलघाट टाइगर कॉरिडोर एक संवेदनशील क्षेत्र है। जिसके एक किमी के दायरे तक उत्खनन प्रतिबंधित है, उक्त स्थल पर वन विभाग को निगरानी रखना चाहिए।

**आदिल खान, पत्रकार कल्याण परिषद ब्लॉक अध्यक्ष घोड़ाडोंगरी**

# भगवान परशुराम जयंती 30 को, होंगे कई आयोजन

**बैतूल।** सनातन ब्राम्हण महासमाज बैतूल के तत्वावधान में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान परशुराम जयंती एवं सामूहिक उपनयन संस्कार कार्यक्रम भगवान परशुराम मंदिर बडोरा में मनाया जायेगा। इस अवसर पर हवन-पूजन एवं भंडारा आयोजित होगा। समाज के अध्यक्ष पं. सुभाष मोहन पाण्डेय, कार्यक्रम संयोजक पं. राजेश अवस्थी ने बताया कि 30 अप्रैल बुधवार को सुबह 7 बजे से भगवान शिव परशुराम का अभिषेक एवं हवन-पूजन होगा। सुबह 8 बजे सामुहिक उपनयन संस्कार, दोपहर 12 बजे आमंत्रित अतिथियों द्वारा आर्शीवाद वचन एवं बैतूल में जनप्रतिनिधियों का सम्मान, दोपहर 2 बजे से भोजन प्रसादी वितरित की जायेगी। समाज के अध्यक्ष पं. सुभाष मोहन पाण्डेय, कार्यक्रम संयोजक पं. राजेश अवस्थी ने सभी स्वजातीय बंधुओं से कार्यक्रम में उपस्थित होने की अपील की है।

# आरपीएफ कोर्ट ने 280 व्यक्तियों से दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला

### बैतूल थाना कार्यवाही में सबसे अव्वल रहा

**बैतूल।** रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) थाना बैतूल ने रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे न्यायालय भोपाल का शिविर आयोजित कर 280 व्यक्तियों से दो लाख 22 हजार रुपए से अधिक राशि का जुर्माना जमा कराया। कार्यवाही में बैतूल थाना सबसे अव्वल रहा है,जिसमें सर्वाधिक एक लाख से अधिक की राशि 153 व्यक्तियों से जमा कराई गई। कोर्ट कैंप में बैतूल के अलावा भोपाल,इटारसी, हरदा एवं आमला आरपीएफ थाने के मामलों का निराकरण किया गया। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) बैतूल थाना प्रभारी राजेश बनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को रेलवे न्यायालय भोपाल के न्यायाधीश अनुराग खरे की विशेष उपस्थिति में आरपीएफ थाना बैरक के सामने कोर्ट कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान आरपीएफ थाना बैतूल द्वारा रेल परिसर में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले,अवैध रूप से खान पान की सामग्री बेचने वाले , महिला यात्री के डब्बे में प्रवेश करने , दिव्यांग यात्री के डब्बे में प्रवेश करने,पायदान पर यात्रा करने, नो पार्किंग में वाहन पार्क करने,रेल परिसर में गंदगी फैलाने वालों के खिलाप रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 153 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक लाख 13 हजार 740 रुपए का अर्थ दंड वसूला। कोर्ट कैंप के दौरान भोपाल एवं इटारसी थाने के 88 मामले तथा हरदा एवं आमला के 39 मामलों का भी निराकरण कर अर्थ दंड से दंडित किया। कैंप में ऐसे कुल 280 व्यक्तियों पर कार्यवाही करते हुए उनसे दो लाख 22 हजार 295 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इस कार्यवाही में आरपीएफ थाना बैतूल के निरीक्षक थाना प्रभारी राजेश बनकर, उप निरीक्षक विद्याधर यादव,सहायक उप निरीक्षक डी.के. देशमुख, राकेश मिश्रा,सोबरन सिंह, सुभाष मीणा, प्रधान आरक्षक संतोष पटेल,फराह खान, कुलवंत, मनजीत, बोस्निंदर एवं धर्मेंद्र का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने रेल नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को पकडक़र न्यायालय में प्रस्तुत किया। कोर्ट कार्यवाही अशोक सोनी एवं कोर्ट स्टाफ ने व्यवस्थित तरीके से सम्पन्न कराई।

### रेल नियमों का कड़ाई से पालन करें

आरपीएफ थाना प्रभारी राजेश बनकर ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे रेल नियमों का कड़ाई से पालन कर पायदान पर बैठकर यात्रा नहीं करें, बिना अधिकार पत्र के रेल परिसर में प्रवेश नहीं करें, बिना उचित कारण के खतरे की जंजीर नहीं खींचे, विकलांग एवं महिलाओं के लिए निर्धारित कोच में नहीं बैठे तथा किसी भी अनजान व्यक्तियों से खाने पीने की वस्तुएं नही ले।

## बुजुर्गों पर शोध के लिए सीमा बर्डे को मिली पीएचडी की उपाधि

**बैतूल।** शासकीय कन्या महाविद्यालय सदर बैतूल के गृह विज्ञान विभाग में पदस्थ श्रीमती सीमा बेलवंशी बर्डे को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। उन्होंने बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के अंतर्गत संचालित सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल में प्रो.डॉ.लक्ष्मी अग्निहोत्री के मार्गदर्शन में शोध कार्य पूर्ण किया। उनके शोध का विषय बैतूल जिले के वृद्ध आश्रम में रहने वाले एवं परिवार के साथ रहने वाले वृद्धों का मनोवैज्ञानिक तुलनात्मक अध्ययन रहा। जिसमें उन्होंने दोनों वर्गों के मानसिक स्वास्थ्य भावनात्मक स्थिति और सामाजिक जुड़ाव को लेकर गहन अध्ययन किया। इस महत्वपूर्ण शोध कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में उनके पिता सज्जन लाल बेलवंशी, माता शांति बेलवंशी एवं भारतीय रेलवे में पदस्थ पति दीपक कुमार बर्डे का विशेष सहयोग एवं प्रोत्साहन रहा। सीमा बेलवंशी बर्डे की इस उपलब्धि से बैतूल जिले की शैक्षणिक और सामाजिक पहचान को नई दिशा मिली है।

# भाजपा ने जलाया राहुल एवं सोनिया का पुतला

**बैतूल।** प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सोनिया गांधी और राहूल गांधी के खिलाफ चार्ज सीट दाखिल करने के मामले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व एपीए की पूर्व नेता सोनिया गांधी का पूतला नगर के लल्री चौक पर जलाया इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पंवार ने कहा कि नेशनल हेलार्ड मामला काले धन को सफेद करने का गांधी मॉडल है। भ्रष्टाचारी नेताओ पर मामला बनने के बाद कांग्रेस जिस हिसाब से शोर मचा रही है। उसे चोर मचाए शोर कहा जा सकता है। जहां पार्टी का पैसा निजी पुंजी में बदल जाता है। सार्वजनिक संपत्ति पारिवारिक संपत्ति बन जाती है ऐसा कांग्रेस में ही होता है। भाजपा का स्पस्ट मत है कि यह कोई वैचारिक हमला नही बल्कि न्याय की दिशा में कानूनी कार्यवाही है। ऐजेएल की संपत्ति का उददेश्य पत्रकारिता और जनसेवा था लेकिन मॉ बेटे ने इसे गांधी परिवार की रियल स्टैट कंपनी में बदल दिया। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भास्कर मगरदे ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानीयों द्वारा खडी की गई संस्थाओ को निजी लाभ के लिए कब्जा करने का पाप सोनिया गांधी और राहूल गांधी ने किया है यह बलिदानियों का भी अपमान है। कांग्रेस पूरी तरह से पारिवारिक उदयम बन चुकी है जहां लोकतंत्र नही है। चाटुकारिता का ईनाम मिलता है और पारदर्शीता से बचा जाता है जिस तरह से कांग्रेस के नेता ईडी की कार्यवाही पर विरोध कर रहे है। वह न्याय की राह में बांधा डालने का काम कर रहे है यह प्रदर्शन लोकतंत्र मे ही गांधी परिवार के लिए राजनैतिक नाटक है। पूतला दहन कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद ज्योति धुर्वे, पूर्व जिलाध्यक्ष वंसत बाबा माकोडे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, मंडल अध्यक्ष विकास मिश्रा, नपाउपाध्यक्ष महेश राठौर, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष महेश्वर सिंह चंदेल, जिला उपाध्यक्ष रश्मि साहू, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष ममता मालवी, सुनिता देशमुख, उमेश राठौर, सहित बडी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहें।

# एअर-इंडिया की एयर होस्टेस की कार नहर में गिरी, मौत

## भोपाल में दोस्तों के साथ घूमने निकली थी; सामने गाय आने से गाड़ी बेकाबू हुई

**भोपाल (नप्र)।** भोपाल में गुरुवार रात एक तेज रफ्तार कार कोलार नहर में गिर गई। हादसे में एअर इंडिया की एयर होस्टेस हर्षिता शर्मा (21) की मौत हो गई। वह अपने दो दोस्तों के साथ घूमने निकली थी। कार चला रहे दोस्त जय ने बताया कि सामने अचानक गाय आ गई, जिसे बचाने की कोशिश में कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी।

हर्षिता को गंभीर हालत में एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। हादसे में दो दोस्तों को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने गाड़ी चला रहे जय के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज किया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं।

**भाई से कहा था- बर्थ डे पर भोपाल आऊंगी-** एयर होस्टेस हर्षिता के पिता प्रदीप शर्मा ने बताया कि वह अक्सर शहर से बाहर रहती थी। बुधवार रात उसने भाई को वॉट्सऐप पर बताया था कि शुक्रवार को भोपाल आ रही है। हमें नहीं पता था कि वह गुरुवार को ही भोपाल

पहुंच गई थी। वह मिनाल रेसीडेंसी के पास होटल में रुकी थी।

**दोस्तों ने फोन पर बताया- वो अस्पताल में है-** परिजन को हादसे की जानकारी तब मिली, जब हर्षिता की दोस्त शिवानी का कॉल आया कि वह अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि हर्षिता ब्रेन डेड हो चुकी है। शुक्रवार सुबह उसे मृत घोषित कर दिया गया।

**दोस्त बोले- हर्षिता ने साथ घूमने बुलाया था-** पुलिस के मुताबिक गुरुवार रात हर्षिता अपने दोस्त सुजल और जय के साथ कार में कोलार इलाके में घूम रही थी। जय गाड़ी चला रहा था। कोलार के होली क्रॉस स्कूल के पास पुल पर कार के सामने गाय आ गई, जिसे बचाने की कोशिश में गाड़ी नहर में गिर गई। जय और सुजल ने हर्षिता को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। जय ने पुलिस को बताया कि वह और सुजल एमबीए के छात्र हैं और हर्षिता के कॉल पर ही मिलने पहुंचे थे।

## भोपाल की सरकारी बिल्डिंग में दो मजार

**भोपाल (नप्र)।** भोपाल की सरकारी बिल्डिंग में दो मजारें बना ली गई हैं। बकायदा यहां इबादत भी की जा रही है। हिंदूवादी संगठन ने इसे लैंड जिहाद बताते हुए एसडीएम से शिकायत की है।

मामला भोपाल के शासकीय आवासीय क्षेत्र 1250 का है। संस्कृति बचाओ मंच ने इस पर आपत्ति जताई है। मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा- 1250 इलाके में आवास क्रमांक-28, 38 और 85, 96 के आसपास दो मजारों का निर्माण अवैध रूप से किया गया है। वीवीआईपी इलाके के सरकारी भवन में दो मजारें कैसे बन गईं? भोपाल में लैंड जिहाद चल रहा है।

**करीब तीन साल पहले बनाई गई मजारें-** तिवारी ने गुरुवार को टीटी नगर एसडीएम अर्चना रावत को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। कहा कि इन मजारों को हटवाने की कार्रवाई करें ताकि बेशकीमती भूमि अतिक्रमणमुक्त हो सके। यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आंदोलन किया जाएगा।

इस पर एसडीएम रावत ने शुक्रवार सुबह पटवारी को मौके पर भेजा। जांच में सामने आया है कि मजारें करीब तीन साल पुरानी हैं। इन्हें किसने बनाया या बनवाया, ये साफ नहीं हो पाया है। इन मजारों के आसपास मुस्लिम फैमिली रहती हैं। मजार के सामने ही बाघमेश्वरी देवी मंदिर है।

**कोलार एसडीएम का इलाका, जानकारी दे रहे-** पटवारी की जांच रिपोर्ट की जानकारी देते हुए एसडीएम अर्चना रावत ने कहा- जिस इलाके में मजारें बनाई गई हैं, वह कोलार एसडीएम के क्षेत्र में आता है। मामला वहां पहुंचाया जाएगा। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी को भी इसकी जानकारी दे रहे हैं ताकि वो सही जगह शिकायत कर सकें। उचित कार्रवाई होगी।

## मध्यप्रदेश में पहली बार युवा कांग्रेस की मेम्बरशिप लॉन्च

**भोपाल (नप्र)।** भोपाल की कांग्रेस कमेटी कार्यालय में शुक्रवार को युवा कांग्रेस संगठन (आईएनएस) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आईएनएस ने मध्यप्रदेश में पहली बार ब्लॉक, विधानसभा, जिला और राज्य स्तर पर पार्टी के चुनाव और मेंबरशिप का ऐलान किया है।

आईएनएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि अब ऐसा दौर शुरू हो रहा है, जब पार्टी के युवा नेता सीधे चुनाव के माध्यम से चुने जाएंगे, न कि उन्हें नामांकित किया जाएगा। यह बदलाव भारतीय राजनीति के लिए ऐतिहासिक है और यह सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। इससे पहले भी आईएनएस आंतरिक चुनाव कर चुका है।

**निष्पक्षता के लिए राज्य स्तर पर टीम बनाई गई-** राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि यह कदम राहुल गांधी के विजन का हिस्सा है, जब वे साल 2008 में आईबायसी और एनएसयूआई के प्रभारी थे। इस प्रक्रिया से हर क्षेत्र के युवकों को राजनीति में उतरने का मौका मिलेगा। वहीं, चुनावों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जोनल और राज्य स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसर्स की टीम तैनात की गई है।

इसके लिए एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया है। जिसमें 27 अप्रैल 2025 से 6 मई 2025 तक नामांकन चलेगा। 7 से लेकर 9 मई तक स्क्रूटनी का काम किया जाएगा। उसी के आधार फाइनल कैंडिडेट की लिस्ट 11 मई तक प्रकाशित होगी।

## बदनावर में कंटेनर और कार की टक्कर ,एक की मौत

**बदनावर (नप्र)।** बदनावर के पेटलावद रोड स्थित नागेश्वर मंदिर के पास शुक्रवार सुबह एक सड़क हादसा हुआ। करीब 8 बजे तेज रफ्तार कंटेनर और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार राजगढ़ निवासी पूजा जैन (32) की

मौके पर ही मौत हो गई। उनके पति नयन जैन (34) गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार उज्जैन स्थित ससुराल से राजगढ़ लौट रहा था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार की ड्राइवर साइड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कंटेनर में लगा पाइप गाड़ी चला रहे नयन के हाथ को फाड़ता हुआ पीछे की सीट पर बैठी पूजा के गले में जा घुसा। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।राहगीर अनिल बैरागी और अन्य लोगों ने आरी से पाइप को काटकर नयन के हाथ को निकाला। कार में सवार जुड़वा बेटियां और नयन के भाई चयन जैन को मामूली चोटें आईं। 108 एम्बुलेंस से घायलों को बदनावर अस्पताल लाया गया।

# विवेकानंद एकेडमी परिसर में विश्व विरासत दिवस पर सोहागपुर के इतिहास का वर्णन, छात्रों से प्रश्नोत्तरी

**हीरालाल गोलानी सोहागपुर।** विवेकानंद एकेडमी परिसर में विश्व विरासत दिवस पर सोहागपुर के इतिहास पर व्याख्यान माला का आयोजन भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, क्षेत्रीय निदेशक मध्य क्षेत्र कार्यालय एवं मंदिर सर्वेक्षण परियोजना भोपाल के संयुक्त तत्त्वावधान में किया गया। कार्यक्रम क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह के आतिथ्य एवं नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लता यशवंत पटैल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।इस अवसर पर डॉ भुवन विक्रम क्षेत्रीय निर्देशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, डॉ सुश्री मिश्रा विक्रम अधीक्षण पुरातत्वविद मंदिर सर्वेक्षण परियोजना, डॉ जलज कुमार तिवारी उप अधीक्षण पुरातत्वविद, डॉ राजेश कुमार मेहर सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् मंदिर सर्वेक्षण, ईशानंद सरस्वती, समाजसेवी कन्नूलाल अग्रवाल, पूर्व विधायक सविता दीवान आदि मंचासीन थे। कार्यक्रम का संचालन वकील प्रांजल तिवारी ने किया। इस अवसर पर व्याख्यान माला में डॉक्टर भुवन विक्रम, डॉ,जलज तिवारी, डॉ श्रीमती मिश्रा विक्रम डॉ राजेश मेहर आदि ने सोहागपुर के पुरातात्त्विक इतिहास, महत्त्व, संरक्षण तथा जागरूकता पर विस्तृत व्याख्यान देते हुए बताया कि सोहागपुर का इतिहास 1500 वर्ष से पूर्व का है, कई इतिहासकार 40 हजार वर्ष का इतिहास बताते हैं।इसी क्रम में पुरातत्ववेत्ताओं ने प्रोजेक्ट के माध्यम से सोहागपुर के इतिहास का भी वर्णन बताया। इसकी के साथ विवेकानंद एकेडमी परिसर में इतिहास पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। वहीं करीबन विभिन्न शालाओं के करीबन 30 छात्र छात्राओं से डाक्टर भुवन विक्रम ने

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करके वाद संवाद किया गया। करीबन तीन घंटे तक व्याख्यान माला में सारगर्भित उल्लेख से गणमान्य नागरिक को सोहागपुर के इतिहास की जानकारी से अवगत कराया गया।

क्षेत्रीय विधायक विजयपाल सिंह ने विवेकानंद स्कूल क संचालक अनिल गहरैया, एवं वकील प्रांजल तिवारी को बधाई देकर कहा यह एक अद्भुत कार्यक्रम आयोजित किया गया सोहागपुर का इतिहास आज हमने देखा एवं सुना सोहागपुर का इतिहास बच्चों को जानना चाहिए ।कि हम एक बड़ा पौराणिक शहर के निवासी है।

छात्र मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। मोबाइल में अपने भारत की विरासत को देखें इतिहास देखें यह महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद विद्यालय प्रिंसिपल अनीता गहरैया सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इसी अवसर पर सुभाष पटैल के द्वारा प्रदत्त यथार्थ गीता के प्रतियां प्रदान की गई।इन प्रतियो को अतिथियों एवं सहभागिता करने वालों को प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि अयोध्या में मंदिर सर्वेक्षण में डाक्टर भुवन विक्रम भी शामिल थे।

# ट्रक ने बाइक को रौंदा, पिता-दो बच्चों की मौत

## दो बच्चे गंभीर घायल, टायर के नीचे दब गए शव; खजुराहो में एक गाड़ी पर 5 लोग सवार थे

**खजुराहो (नप्र)।** छतरपुर के खजुराहो में ट्रक ने बाइक सवार परिवार को रौंद दिया। पिता और दो बच्चों की मौके पर मौत हो गई। शव ट्रक के टायरों के नीचे दब गए। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया।

हादसा देवगांव के पास झमटुली रोड पर शुक्रवार सुबह 8.30 बजे हुआ। हादसे में मिजाजी लाल अहिरवार (25), उनके बेटे शिवम (2) और बेटी भावना (3) की मौत हो गई। परिवार के दो अन्य बच्चे बादल (6) और काजल (5) गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। परिजन एक करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं।ग्रामीणों ने बताया, पुलिस हादसे के करीब डेढ़ घंटे बाद पहुंची। जबकि गांव से 5 किलोमीटर दूर देवगांव पुलिस चौकी है। यहां पास में 100 डायल भी खड़ी रहती है।

**निमंत्रण से वापस अपने गांव लौट रहा था परिवार-** परिवार ओटापुरवा में रिश्तेदार के यहां गया था और वापस अपने गांव भैरा लौट रहा था। ग्रामीण पुष्पेंद्र अहिरवार ने बताया, मिजाजी लाल अपने बच्चों को बाइक पर बिठाकर घुमा रहा था। उसकी पत्नी रिश्तेदारों से मिल रही

थी। उन्हें थोड़ी देर बाद अपने घर रवाना होना था, जैसे वह गली से बाहर निकले और ट्रक ने रौंद दिया।

**पुलिस के नहीं आने पर लोगों ने जाम लगाया-** स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के बाद प्रशासन को कई बार फोन किया, लेकिन डेढ़ घंटे बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीण सड़क पर बैठ गए। जाम के बाद बमीठा थाने से दो कॉन्स्टेबल मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिजाजी लाल परिवार के साथ ओटा पुरवा में भांजे राकेश अहिरवार की शादी में शामिल होने आया था। 15 अप्रैल को शादी थी। गुरुवार 17 अप्रैल को रिसेप्शन के बाद लौट रहे थे। हादसे के बाद शादी वाले घर में मातम छा गया।

## मनावर में बारातियों से भरी बस पलटी, महिला की मौत,12 घायल

**मनावर (नप्र)।** मनावर में मान नदी किनारे ब्रेक फेल होने से बारातियों से भरी बस पलट गई। हादसे में नागदा जंक्शन की बबीता (35) की मौत हो गई। हादसे में 12 से ज्यादा बाराती घायल हुए हैं। घटना शुक्रवार सुबह 10.30 बजे की है।दरअसल, नागदा जंक्शन से बारात बड़दा पुर्नवास जा रही थी। बस में सवार बाराती मान नदी में नहाने के लिए रुके थे। नहाने के बाद जब सभी बस में बैठे, तब अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया। जिससे वह नदी के समीप गड्ढे में जा गिरी।

**कूदकर जान बचाने की कोशिश कर रही थी महिला-** मृतक बबीता के दो बच्चे हैं। दूल्हे राजपाल सिंह के पिता भगवान सिंह ने बताया कि बबीता कूदकर जान बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान बस उनके ऊपर पलट गई। बाकानेर बीएमओ डॉ. वीरेंद्र कुमार धारवे ने मौके पर बबीता की मृत्यु की पुष्टि की। बाकानेर चौकी प्रभारी अश्विन चौहान ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है और राहत कार्य जारी है। पुलिस घायलों की पहचान कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है।

# जिम में कारोबारी को आया हार्ट अटैक, मौत

## जबलपुर में डंबल रखने के बाद अचानक नीचे गिर पड़े

**जबलपुर (नप्र)।** जबलपुर में जिम में एक्सरसाइज कर रहे एक कारोबारी को हार्ट अटैक आ गया। जिससे उसकी मौत हो गई। ये घटना शुक्रवार सुबह करीब 7.30 बजे की है। इसका वीडियो भी सामने आया है।

मृतक का नाम यतीश सिंघई (उम्र 51 वर्ष) है, जो पेशे से कारोबारी थे। यतीश रोजाना करीब एक से डेढ़ घंटे तक जिम में एक्सरसाइज करते थे। शुक्रवार सुबह वे अचानक नीचे गिर पड़े। जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि यतीश सिंघई हाथ में डंबल लिए जा रहे है। तभी कुछ परेशानी महसूस होने पर वे डंबल को नीचे रख देते है। इस दौरान उनकी चाल धीमी हो जाती है। वे थोड़ी आगे बढ़ते हैं और फिर अचानक नीचे गिर पड़ते हैं।

ये देखकर उनके ट्रेनर और बाकी लोग उनके पास पहुंचते हैं। उनकी पीठ और सीने पर मालिश करते हैं। कोई हरकत नहीं देख उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाते हैं।अस्पताल में जरूरी जांच के

बाद डॉक्टर ने यतीश को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, यतीश की मौत दिल का दौरा (हार्ट अटैक) पड़ने से हुई।

**सीने में दर्द था, फिर भी एक्सरसाइज की-** यतीश सिंघई शहर के गोरखपुर थाना क्षेत्र स्थित गोल्ड जिम में पिछले कई महीनों से नियमित रूप से एक्सरसाइज करने आ रहे थे।यतीश के ट्रेनर ने बताया कि सुबह जब वह जिम आए थे, उस दौरान उनको हल्का-हल्का सीने में दर्द हो रहा था, तब उन्हें आराम करने की सलाह दी गई थी। यह भी कहा था कि आज एक्सरसाइज न करें और ज्यादा वजन भी न उठाए। इसके बाद भी वह हैवी वेट से प्रेक्टिस कर रहे थे।

**डॉक्टर बोले- हार्ट अटैक की कोई एक वजह नहीं होती-** कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. दिलीप तिवारी ने बताया कि हार्ट अटैक आने की कोई एक वजह नहीं होती। देर रात तक जागना और जल्दी उठना, डाइट फॉलो न करना, नशा करना जैसे कई कारण हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा जिनको कोरोना हुआ था, उन्हें भी सावधानी की जरूरत है। वहीं, गोरखपुर थाना प्रभारी नितिन कमल ने कहा-अभी तक थाने में कोई जानकारी नहीं आई है। परिवार वाले भी थाने नहीं पहुंचे हैं। यह जरूर है कि आज सुबह जिम में एक व्यक्ति की मौत हुई है, इसका कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है।

### कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर समर्पित होकर कार्य करना होगा तभी हमारा मिशन मप्र सफल और सशक्त होगा: हरीश चौधरी

# देश का खजाना खाली कर दिया : जीतू पटवारी

**भोपाल ।** मप्र कांग्रेस के प्रभारी श्री हरीश चौधरी (विधायक) और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने आज छतरपुर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक ली।

मप्र प्रभारी श्री हरीश चौधरी ने कहा कि कि देश तानाशाही ने नहीं, विचारों और विजन से चलता है, देश में मोदी का और प्रदेश में मोहन यादव का विकास और जनता के अधिकारों, सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए कोई विजन नहीं है, वे तो जनता को भ्रमित कर केवल टेलीविजन पर अपनी छवि चमकाने में माहिर हैं। कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस संगठन के लोग जब जनता की आवाज बनकर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट और सक्रिय रहेंगे तो हर तानाशाही ध्वस्त हो जायेगा। श्री चौधरी ने पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ताओं से संवाद कर समग्रता एवं सामंजस्य की सोच के साथ संगठन का विस्तार हर गांव, गली, मोहल्ले तक करने की बात कहीं। उन्होंने कहा कि यह समय संगठन के नवसृजन का है और एक-एक कार्यकर्ता को जमीनी स्तर पर पार्टी के प्रति समर्पित होकर कार्य करना होगा तभी

हमारा मिशन मध्यप्रदेश सफल और सशक्त होगा।

श्री पटवारी ने आज छतरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुये संगठन की मजबूती और भाजपा सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार आदि मुद्दों पर संवाद किया। उन्होंने कहा कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश की जनता से जो वादे किये थे कि बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, किसानों के साथ न्याय करेंगे, लेकिन मोदी राज में न बेरोजगारी दूर हुई, न महंगाई कम हुई और न ही किसानों को न्याय मिला, उल्टा किसानों पर लगातार अत्याचार हुअ है। बहुत हुई महंगाई की मार लेकिन आज पांच गुना महंगाई देश में बढ़ गई है। विश्वगुरू बनाने वाले मोदी ने आज देश की 78 प्रतिशत संपत्ति 13 प्रतिशत लोगों, अड़ानी और अंबानी के हाथों में दे दी है, और 80 प्रतिशत के पास मात्र 20 प्रतिशत संपत्ति बची हैं, यह कैसा देष है। मोदी ने देश का खजाना खाली कर दिया। धाना एक छोटा देश है, पासपोर्ट को लेकर लिस्ट आई, फोर्स की एक लिस्ट आई जिसमें दुनिया के सबसे 100 मजबूत प्रभावी लोगों की लिस्ट आई, उसमें इंडिया का नाम ही नहीं।

श्री पटवारी ने कहा कि हम सभी के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी ने देश में जाति जनगणना की बात कहीं, वे जाति जनगणना कराना चाहते हैं, लेकिन भाजपा इसका विरोध करती है। आखिर क्या है जाति जनगणना, गरीबों का सर्वे, किस जाति में कितने गरीब हैं, उस गरीब की पहचान है जाति जनगणना उनके लिए देश के खजाने के द्वार खुले, मंदिर में पूजा करने वाला गरीब पुजारी की पहचान है जाति जनगणना, अमीर और गरीब की खाई दूर करना है जाति जनगणना, सरकार ऐसे गरीबों की मदद कर सके इसलिए आवष्यक है जाति जनगणना।

श्री पटवारी ने कहा कि आज किसान आत्महत्या में देश विश्व में नंबर वन पर है। चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया, भाजपा के लोगों के अलग-अलग बयान आये, पूरे बुंदेलखंड से तीन गुना जमीन पर चाईना ने जमीन पर कब्जा कर लिया, बंगलादेश, जिसका निर्माण इंदिरा जी ने किया उसका राष्ट्रपति मोदी जी को चार बातें सुनाकर जाता है, लेकिन मोदी जी के हलक से एक शब्द नहीं निकलता हैं।

## मध्य प्रदेश में जल संकट पर बीजेपी सरकार की नाकामी : मुकेश नायक

**भोपाल।** मध्य प्रदेश में जल संकट की समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है और यह संकट अब राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमा चुका है। लाखों लोग पीने के पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसने उनकी जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने इस गंभीर स्थिति के लिए बीजेपी सरकार की नीतियों और कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार की निष्क्रियता, भ्रष्टाचार और जनविरोधी फैसलों ने मध्य प्रदेश की जनता को इस संकट की आग में झोंक दिया है। यह एक ऐसा संकट है जो केवल कागजी योजनाओं और बड़े-बड़े वादों से हल नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए ठोस कदमों और जवाबदेही की जरूरत है, जो बीजेपी सरकार में कहीं नजर नहीं आती। राज्य के अलग-अलग हिस्सों से जल संकट की ऐसी कहानियाँ सामने आ रही हैं जो दिल दहला देने वाली हैं और सरकार की विफलता को साफ तौर पर उजागर करती हैं। इछावर विधानसभा क्षेत्र, जो राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का अपना क्षेत्र है, वहां की स्थिति बेहद चिंताजनक है। यह सोचने वाली बात है कि एक मंत्री के क्षेत्र में भी लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 18 साल के लंबे कार्यकाल के बावजूद, इस क्षेत्र के गांवों में आज भी मूलभूत जल सुविधाओं का अभाव है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि सरकार ने न केवल आम जनता की अनदेखी की है, बल्कि अपने ही नेताओं के क्षेत्रों को भी राहत देने में असफल रही है। ग्रामीणों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और उनकी यह मजबूरी सरकार की उदासीनता का जीता-जागता सबूत है।

## ॥ मंदिरम् ॥

87

### करणी माता मंदिर, बीकानेर, राजस्थान

25000 चूहों के कारण मशहूर है बीकानेर का करणी माता का मंदिर, चूहों को मारने पर मिलती है सजा। करणी माता का मन्दिर एक प्रसिद्ध हिन्दू मन्दिर है जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। इसमें देवी करणी माता की मूर्ति स्थापित है। यह बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में देशनोक में स्थित है। करणी माता का जन्म चारण क्षत्रिय कुल में हुआ यह मन्दिर चूहों का मन्दिर भी कहलाया जाता है। मन्दिर में सफेद चूहे का दर्शन मंगलकारी माना जाता है। इस पवित्र मन्दिर में लगभग 25000 चूहे रहते हैं। बीकानेर में करणी माता का मंदिर पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है। यह मंदिर करणी माता को समर्पित है। यहां रहने वाले लोगों का मानना है कि करणी माता लोगों की रक्षा करने वाली देवी दुर्गा का अवतार हैं। करणी माता चारण जाति की योद्धा ऋषि थीं। एक तपस्वी का जीवन जीते हुए, यहां रहने वाले लोगों के बीच वह पूजी जाते थे। जोधपुर और बीकानेर के महाराजाओं से अनुरोध प्राप्त करने के बाद, उन्होंने मेहरानगढ़ और बीकानेर किलों की आधारशिला भी रखी। हालांकि उन्हें समर्पित कई मंदिर हैं, लेकिन बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक शहर में स्थित इस मंदिर की सबसे ज्यादा मान्यता है।

# मप्र में अब सरकारी स्कूलों के टीचर्स की अटेंडेंस चेहरा दिखाकर लगेगी

## स्कूल शिक्षा विभाग ने लोकेशन आधारित उपस्थिति की तैयारी की शुरू

- नया सिस्टम जुलाई से किया जाएगा अनिवार्य
- कुछ जिलों में शिक्षक नहीं जाते। उनके स्थान पर दूसरे लोग पढ़ाने जाते हैं

**भोपाल (नप्र)।** अब सरकारी स्कूलों से शिक्षक गायब नहीं रह पाएंगे। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। प्रदेश के करीब चार लाख शिक्षकों की उपस्थिति सार्थक एप के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज होगी। यह एप शिक्षकों की लोकेशन दर्ज करेगा साथ ही आनलाइन चेहरा दिखाई देने पर ही उपस्थिति लगेगी। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलेंगे तो जुलाई से शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य कर दी जाएगी।

प्रदेश के 99,145 स्कूलों में से केवल 8,051 स्कूलों में ही शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति एम शिक्षा मित्र एप से दर्ज की जा रही है यानी 91,094 स्कूलों में इसका उपयोग ही नहीं हो रहा है।

जबकि यह व्यवस्था अनिवार्य की गई थी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सवाल खड़े होते रहते हैं।

स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी इस बात को कई बार स्वीकार कर चुके हैं कि प्रदेश में कुछ जिलों में शिक्षक स्कूल नहीं जाते हैं। उनके स्थान पर दूसरे लोग पढ़ाने जाते हैं। वहीं कुछ शिक्षक स्कूलों के निर्धारित समय पर नहीं पहुंचते हैं।

### तीन बार व्यवस्था बनाई गई लेकिन फेल हो गई

- स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2017, वर्ष 2020 और वर्ष 2022 में प्रयास किया।
- ऑनलाइन उपस्थिति एम शिक्षा मित्र एप के जरिए शुरू की गई थी।
- लेकिन शिक्षकों ने इस प्रक्रिया का विरोध किया।
- कभी स्मार्ट फोन न होने तो कभी नेटवर्क न मिलने का बहाना बनाया गया।
- ऑनलाइन उपस्थिति से कन्नी काटी जाती रही।
- कई कारणों से यह प्रक्रिया ठीक से लागू नहीं हो पाई।

### नए एप में गड़बड़ियों को किया गया दूर

एम शिक्षा मित्र एप से उपस्थिति लगानी अनिवार्य की गई थी लेकिन इसके माध्यम से नेटवर्क मिलने पर ही उपस्थिति लगती थी।

इसमें लोकेशन व चेहरा पहचान कर उपस्थिति लगाने का विकल्प नहीं होने से बहुत गड़बड़ियां होती थीं। सार्थक एप में इन्हें दूर कर लिया गया है।

### अवकाश के लिए भी कर सकेंगे आवेदन

सार्थक एप की नई व्यवस्था में कर्मचारी व शिक्षक छुट्टी के लिए भी आवेदन कर सकेंगे और शासन से किसी भी प्रकार का कार्यालयीन पत्राचार इस एप से हो जाएगा।

दरअसल, सार्थक एप मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल से जुड़ा नवीनतम मोबाइल एप्लीकेशन है। सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों की सार्थक एप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इस बार इसे बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा। जुलाई से यह अनिवार्य कर दिया जाएगा।

**– उदय प्रताप सिंह,**
मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग

## 'फ्यूचर रेडी स्किल्स' पहल का शुभारंभ

### 5 लाख से अधिक छात्रों को साइबर सुरक्षा और एआई में दक्ष बनाने की पहल

**भोपाल (नप्र)।** रिलायंस फाउंडेशन और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने मध्यप्रदेश में 'फ्यूचर रेडी स्किल्स' इनिशिएटिव की शुरुआत की। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के 700 कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई संस्थानों में अध्ययनरत 5 लाख से अधिक छात्रों को एड-टेक, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे भविष्य के तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष बनाना है। इस पहल का उद्घाटन भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) में आयोजित 'एमपी फ्यूचर रेडी स्किल्स कॉन्क्लेव' में किया गया। रिलायंस

फाउंडेशन और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने मध्यप्रदेश में 'फ्यूचर रेडी स्किल्स' इनिशिएटिव की शुरुआत। सम्मेलन में विचार साझा करते हुए, मध्यप्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के सचिव आईएएस रघुराज राजेंद्रन ने कहा, कौशल विकास का तात्पर्य केवल प्रशिक्षण नहीं, बल्कि गुणवत्ता, उपयोगिता और समयबद्ध पहुंच है। सभी हितधारकों को समग्र सहयोग से एक प्रभावी स्किल ईको सिस्टम खड़ा करना चाहिए। रिलायंस फाउंडेशन की स्किलिंग प्रमुख नूपुर बहल ने कहा, हमारा विश्वास है कि फ्यूचर रेडी स्किल्स केवल बदलाव से तालमेल बिठाने के लिए नहीं, बल्कि उस बदलाव का नेतृत्व करने के लिए हैं। यह पहल युवाओं को आत्मनिर्भर और तैयार बनाती है। इस मौके पर एनएसडीसी के सीईओ व एमडी वेद मणि तिवारी ने कहा, यह पहल 5 लाख से अधिक छात्रों को व्यवसायिक रूप से सशक्त बनाएगी और भारत को ग्लोबल स्किल हब बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।

### चीता प्रोजेक्ट का विस्तार कर गांधीसागर अभयारण्य में 20 अप्रैल को छोड़ेंगे चीते

**भोपाल ।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश की धरती पर चीता प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। भारत और लगभग सम्पूर्ण एशिया महाद्वीप से विलुप्त हो चुके चीतों का पुनर्वास कर राज्य सरकार प्रकृति से प्रगति और प्रगति से प्रकृति के संरक्षण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज ही केन्द्रीय पर्यावरण, वन एनं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के साथ मिलकर चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। इसमें तय किया कि मध्यप्रदेश में चीता प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा। केन्द्रीय मंत्री ने कूनो नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाए जाने सहित अन्य कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिन पर राज्य सरकार शिद्दत से अमल करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को मीडिया को जारी संदेश में यह विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क के बाद मंदसौर में गांधीसागर अभयारण्य प्रदेश का दूसरा ऐसा स्थान होगा, जहां चीतों को बसाया जा रहा है। हम चीता प्रोजेक्ट के विस्तार की स्वीकृति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के आभारी हैं। आगामी 20 अप्रैल को गांधीसागर अभयारण्य से मध्यप्रदेश में चीता प्रोजेक्ट का विस्तार करने जा रहे हैं।

# पति की हत्या के बाद नाबालिग पत्नी ने प्रेमी को किया वीडियो कॉल

## खून से सनी लाश दिखाकर आशिक से बोली– काम हो गया

**बुरहानपुर (नप्र)।** इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर आईटीआई कॉलेज के पास मिले युवक के शव मामले में पुलिस ने अंधेकत्ल का राजफाश हो गया। युवक राहुल की हत्या उसकी नाबालिग पत्नी ने ही की है। अपने प्रेमी के दोस्त जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है को हत्या की सुपारी दी गई थी, खास बात यह है कि प्रेमी युवराज हत्या के दौरान घटनास्थल पर मौजूद नहीं था।

राहुल की पत्नी उसे शॉपिंग के नाम पर ले गई। रास्ते में चप्पल गिराई और पीछे से आ रहे प्रेमी के दोस्तों के साथ राहुल की हत्या को अंजाम दिया। बताया जा रहा है आरोपित पत्नी नाबालिग है, राहुल उससे दस साल बड़ा था, प्रेमी के साथ मिलकर वो पति को रास्ते से हटाना चाहती थी।

**पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार–** राहुल के हत्या के आरोप में पुलिस ने राहुल की पत्नी और उसके आशिक भारत उर्फ युवराज पुत्र कैलाश पाटिल माली निवासी ग्राम कोदरी, युवराज का दोस्त ललित पुत्र संतोष पाटिल निवासी कोदरी के साथ ही एक नाबालिग को सांवेर (उज्जैन) से गिरफ्तार किया है। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि संदेह के आधार पर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ में युवराज ने स्वीकार किया की उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर राहुल की हत्या का प्लान बनाया था। 12 अप्रैल

की रात्रि आठ से 8.30 बजे प्रेमिका ने उसे वीडियो कॉल कर राहुल का मृत शरीर खून से सना हुआ दिखाया और बोली की काम हो गया है।

**संजय ढाबे पर साथ में खाना खाया, पहला वार भी पत्नी ने किया–** पुलिस ने बताया कि राहुल की पत्नी ने योजना बनाकर युवराज के दो दोस्तों को आईटीआई कॉलेज के आसपास ब्रेकर पर घटना को अंजाम देना तय हुआ। इसकी सूचना अपचारी बालक व ललित को दी थी।

12 अप्रैल को राहुल के साथ उसकी पत्नी शाम छह बजे अपने परिवार वालों को यह बताकर ले गई थी कि हम बुरहानपुर शॉपिंग करने जा रहे हैं। दोनों बुरहानपुर बाजार करने गए। वापसी में पति-पत्नी दोनों ने संजय ढाबे पर खाना खाया। नाबालिग व ललित पुराना आरटीओ बेरियर पर इंतजार कर रहे थे। ललित व नाबालिग दोनों पीछे-पीछे गाडी से चलने लगे।

**रास्ते में चप्पल गिराकर बोली- बाइक रोको–** आईटीआई कॉलेज के सामने ब्रेकर पर राहुल की पत्नी ने बाइक से चलते हुए चप्पल गिरा दी और राहुल को बाइक रोकने का कहा। राहुल ने जैसे ही गाड़ी रोकी तो पीछे से ललित और नाबालिग बाइक से आये और राहुल को पकड़कर रोड किनारे झाड़ियों में ले गए। वहां पर पहले से ही पड़ी हुई बीयर की खाली बोतल से पत्नी ने राहुल के सिर पर मारा, जिससे राहुल बेसुध हो गया। इसके बाद अपचारी बालक एवं ललित ने झाडियों के नीचे गड्ढे में धक्का देकर गिराया फिर वहां पड़ी बीयर की बोतल से राहुल के सिर पर मारी और गुप्ती निकालकर ललित ने राहुल के शरीर पर कई बार वार किए। इससे राहुल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद तीनों रावेर रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से ट्रेन में बैठकर इटारसी चले गए। इटारसी में उतरने के बाद बस से उज्जैन जाने के लिए निकल गए।

### राहुल के शरीर पर किए 35 प्राणघातक वार

राहुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 35 गंभीर चोट के निशान मिले, जो शरीर के अंदर तक थे। बियर की बोतल और गुप्ती से ये वार किए गए।

### पाइप फैक्टरी से जानकारी ले रहा था युवराज

राहुल की हत्या की साजिश रचने के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी युवराज पाटिल शाहपुर स्थित एक पाइप फैक्टरी में ही हमेशा की तरह काम कर रहा था। वह भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। वह पल-पल की जानकारी ले रहा था।

### टाप-जींस पहने घूम रही थी पत्नी

पुलिस आरोपित की पत्नी और उसके साथियों का मेडिकल कराने जिला अस्पताल पहुंची। राहुल की पत्नी ने अपने नाखून में मेहरून कलर की नेल पालिश की थी। वह जींस और टाप पहनी थी। अस्पताल में न तो राहुल की पत्नी और न ही युवराज चेहरे पर कोई शिकन नजर आई। आरोपित ललित ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नंबर-एक शूटर लिख रखा था।

## ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ परामर्श के लिए टेली-मेडिसिन सेवा वरदान : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

### श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में टेली मेडिसिन सेवा का किया शुभारंभ

**भोपाल (नप्र)।** उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र में उन्नत एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाय के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि टेली-मेडिसिन सेवा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवाओं के प्रदाय का सशक्त माध्यम है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में टेली-मेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया। इस सेवा से रीवा और सीधी जिलों के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सकों को वरिष्ठ विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त होगा।

इस सेवा के तहत अब संजय गांधी अस्पताल, रीवा के मेडिसिन, शिशु रोग (पेडियाट्रिक्स) तथा स्त्री रोग (गायनी) विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक, दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत डॉक्टरों को फोन या अन्य संचार माध्यमों से जरूरी परामर्श देंगे। इससे उन मरीजों को तुरंत लाभ मिलेगा जिन्हें विशेषज्ञ सलाह की आवश्यकता होती है। अब ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को विशेषज्ञ सेवाओं के लिए ज़िला मुख्यालय आने की आवश्यकता विशेष परिस्थितियों में ही पड़ेगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि यह सेवा न सिर्फ मरीजों की यात्रा की आवश्यकता को कम करेगी, बल्कि समय, धन और संसाधनों की भी बचत करेगी। साथ ही, इससे प्राथमिक स्तर पर कार्यरत चिकित्सकों को विशेषज्ञों की मदद से त्वरित एवं सटीक निर्णय लेने में सुविधा होगी। इससे मातृ-शिशु स्वास्थ्य, गंभीर बीमारियों की प्रारंभिक पहचान व इलाज की गुणवत्ता में सुधार होगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि टेली-मेडीसिन सेवा का प्रभावी उपयोग सशक्त व स्वस्थ मध्यप्रदेश के विजन को धरातल पर उतारने में सहयोगी होगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने टेली-मेडिसिन कक्ष की व्यस्थाओं का अवलोकन किया एवं विधिवत संचालन के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वे अगले सप्ताह प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा करेंगे। डीन मेडिकल कॉलेज रीवा डॉ. सुनील अग्रवाल सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित थे।

# 16,000 निजी स्कूलों को फीस नियमों में मिली छूट

## 25 हजार से कम फीस, पोर्टल पर जानकारी अपलोड करना जरूरी नहीं

**भोपाल (नप्र)।** 25 हजार रुपए से कम वार्षिक फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों को अब स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर फीस संबंधी जानकारी अपलोड करना जरूरी नहीं होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

विभाग ने साफ किया है कि जिन निजी विद्यालयों द्वारा 25 हजार रुपए से अधिक वार्षिक फीस वसूली जा रही है, उन्हें पोर्टल पर फीस संबंधी जानकारी अपलोड करना

अनिवार्य होगा। इसके लिए अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ा दी गई है। साथ ही, यह भी कहा गया है कि बिना अनुमति और उचित कारण के फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी। प्रदेश में कुल 34,652 निजी स्कूल हैं, जिनमें से लगभग 16,000 स्कूल ऐसे हैं जिनकी किसी भी कक्षा में वार्षिक फीस 25 हजार रुपए या उससे कम है। मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम-2020 के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए निर्धारित फीस संरचना (कक्षा एवं संवर्गवार) की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।

### बिना अनुमति 10 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं फीस

इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि विद्यालय 10 प्रतिशत तक सालाना फीस वृद्धि बिना किसी पूर्व अनुमति के कर सकते हैं। इससे ज्यादा बढ़ाने के लिए संबंधित जिला समिति की अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि अभिभावकों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ न पड़े।

नई उपधारा के तहत, जिन स्कूलों की वार्षिक फीस 25 हजार रुपए से कम है, वे इस अधिनियम के दायरे से बाहर रहेंगे। इसके अतिरिक्त, फीस नियमन एवं संबंधित विषयों के लिए जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर समिति गठित की गई है, जो इन मामलों की निगरानी करेगी।

# 19 अप्रैल को एमपीटी ड्राइव इन सिनेमा में 'राग फेस्ट'

## रेखा भारद्वाज की दिलकश आवाज से सजेगी शाम और लक्ष माहेश्वरी सुनाएंगे दिल को छू लेने वाली कहानियां

**भोपाल।** संगीत और कला प्रेमियों के लिए 19 अप्रैल को होटल लेक व्यू रेसीडेंसी के एमपीटी ड्राइव इन सिनेमा ग्राउंड पर 'राग फेस्ट' का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और बॉलीवुड की मशहूर गायिका रेखा भारद्वाज अपनी दिलकश आवाज़ का जादू बिखेरेंगी। वह सूफी, बॉलीवुड और ग़ज़ल के बेहतरीन गीतों को अपने अनोखे अंदाज़ में प्रस्तुत करेंगी। वहीं जाने-माने स्टोरी टेलर लक्ष माहेश्वरी दिल को छू लेने वाली कहानियों को अपने अनूठे अंदाज में पेश करेंगे। 'राग फेस्ट' का आयोजन एकोएज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

रेखा भारद्वाज राग फेस्ट में भाग लेने शुक्रवार को भोपाल पहुंची। एयरपोर्ट पर उनका वेलकम एको एच मीडिया के ऋषिकेश शर्मा ने बुके देकर किया। रेखा भारद्वाज ने कहा कि भोपाल से मेरा आत्मीय रिश्ता है। राग फेस्ट में पिछले 1 महीने से पूरा भोपाल और राग फेस्ट मेरे गीतों के रंग में रंगा हुआ है। मैं आप सबको मेरे ग्रुप अज़ीज़ों की टोली के संगीत की सुरीली यात्रा पर ले जाऊंगी। आपका इंतेज़ार रहेगा फेस्ट में।इस भव्य संगीतमयी रात का हिस्सा बनने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग डिस्ट्रिक एप पर कर सकते हैं। साथ ही ऑफलाइन टिकट 'गांधी भवन', 'लेकव्यू अशोका होटल', बंसल वन में 'रोमियो लेन' और 10 नंबर पर 'सोल क्लब' से ले सकते हैं। साथ ही इवेंट के दिन 19 अप्रैल को एमपीटी ड्राइव इन सिनेमा में ऑनस्पॉट बॉक्स ऑफिस से भी टिकटस ले सकते हैं।

### भोपाल हुआ रेखामय

इस इवेंट के क्रेज इतना है कि पिछले एक महीने से पूरा भोपाल रेखा भारद्वाज के रंग में रंगा हुआ है। शहर में अलग अलग स्थानों पर कलाकार और यंगस्टर्स रेखा जी के गानों पर जैमिंग कर रहे हैं। यही क्रेज सोशल मीडिया पर भी बना हुआ है। सभी बेसब्री से रेखा जी को लाइव कॉन्सर्ट में सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं।

**रेखा भारद्वाज का संगीतमयी सफर–**रेखा भारद्वाज भारतीय संगीत की दुनिया में एक प्रतिष्ठित नाम हैं। उनके कुछ मशहूर गीतों में 'कबीरा', 'नमक इश्क का', 'ससुराल गेंदा फूल', 'ऐसे क्यों', 'डार्लिंग आंखों से', 'फिर ले आया दिल', 'हमरी अटरिया पे' शामिल हैं। 1997 में 'चाची 420' से अपने गायन करियर की शुरुआत करने वाली रेखा भारद्वाज ने विशाल भारद्वाज और ए.आर. रहमान जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया है। उन्हें 'दिल्ली-6' के 'ससुराल गेंदा फूल' के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार, 'इश्किया' के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, और 'खून माफ' के 'डार्लिंग' के लिए एक बार फिर फिल्मफेयर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

**आयोजकों की प्रतिक्रिया–**एकोएज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुनील शर्मा ने कहा- राग फेस्ट न केवल भोपाल के संगीत प्रेमियों के लिए बल्कि पूरे मध्यप्रदेश के युवाओं और जेन ज़ी के लिए एक अनूठा अवसर है। हम चाहते हैं कि इस आयोजन के माध्यम से भारतीय संगीत की समृद्धि को उजागर किया जाए और इसे एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में स्थापित किया जाए। भोपाल जैसे सांस्कृतिक शहर में इस तरह का आयोजन प्रदेश की संगीत परंपरा को आगे बढ़ाने में सहायक होगा।